नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 058
दि. 30.11.2025,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

“समंदर की ढाल और भारत की शान: नौसेना को मिला स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट ‘तारागिरी’, समुद्री शक्ति में ऐतिहासिक बढ़ोतरी”

(जीएनएस)। नई दिल्ली की सर्द सुबह में जब रक्षा प्रतिष्ठान और नौसेना के शीर्ष अधिकारी मझगांव डॉक शिपबिल्डिंग लिमिटेड (एमडीएल) के विशाल परिसर में एकत्र हुए, तो माहौल में एक अलग ही गर्व, आत्मविश्वास और राष्ट्रशक्ति की अनुभूति थी। कारण था—भारत की समुद्री सुरक्षा को नई धार देने वाला नीलगिरि श्रेणी का चौथा स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट ‘तारागिरी’ भारतीय नौसेना को औपचारिक रूप से सौंपा जाना। यह सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत, आधुनिक तकनीक और समुद्री शक्ति की उस कहानी का अगला अध्याय है, जिसे भारत पिछले कई वर्षों से दृढ़ संकल्प के साथ रच रहा है। जैसे ही युद्धपोत पर तिरंगा फहराया गया, पूरा डॉक क्षेत्र तालियों की गूंज से भर उठा—मानो राष्ट्र ने समंदर पर अपने हक़ और हौसले की एक नई मुहर लगा दी हो।

तारागिरी, प्रोजेक्ट 17-A के तहत बनाई जा रही उन अत्याधुनिक फ्रिगेट श्रृंखलाओं में से एक है, जो पूरी तरह भारतीय डिज़ाइन, भारतीय इंजीनियरिंग और भारतीय दृष्टि का प्रतीक हैं। एमडीएल और जीआरएसई मिलकर 11 फ्रिगेट बना रहे हैं—जो अपने आप में भारत के विशाल शिपबिल्डिंग कौशल और आधुनिक रक्षा निर्माण क्षमताओं का सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन है।

तारागिरी की विशेषता सिर्फ इसकी स्टेल्थ तकनीक नहीं, बल्कि इसकी वह मजबूत विरासत है, जिसे उसके नाम के साथ जोड़ा गया है। पुराने लिएंडर-क्लास फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी ने

33 वर्षों तक समुद्र में अदम्य सेवा दी, और अब आधुनिक ‘तारागिरी’ उसी नाम को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है।

जहाज का डिजाइन ऐसा है कि वह दुश्मन के रडार और निगरानी प्रणालियों से लगभग अदृश्य की तरह गुजर सकता है—युद्धपोत निर्माण में इसे सबसे कठिन तकनीक माना जाता है।

इसके निर्माण में पिछले जहाजों से मिली सीख का इतना प्रभाव पड़ा कि पूरी प्रक्रिया 81 महीने पहले ही पूरी कर ली गई। 75% स्वदेशीकरण, 200 से अधिक भारतीय एमएसएमई की भागीदारी और हजारों लोगों को मिला रोजगार—तारागिरी केवल एक वॉरशिप नहीं, बल्कि भारत के औद्योगिक विकास और आर्थिक उत्थान की कहानी भी है। जहाज के भीतर लगी हाई-टेक प्रणालियाँ आधुनिक समुद्री युद्ध का भविष्य बयान करती हैं। सुपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, 76 मिमी नौसैनिक गन, 30 मिमी और 12.7 मिमी रैपिड फायर हथियार—इन सबकी संयुक्त क्षमता इसे एक ऐसा युद्धपोत बना देती है, जो किसी भी चुनौती के सामने अडिग खड़ा रह सकता है।

इसके गैस टर्बाइन और डीज़ल इंजन का हाइब्रिड प्रणोदन इसे गति, स्थिरता और ऊर्जा दक्षता का बेहतरीन संतुलन देता है।

आज तारागिरी सिर्फ नौसेना में शामिल नहीं हुआ, बल्कि उसने भारत के समंदर में सुरक्षा की एक नई दीवार खड़ी कर दी। यह वह कदम है, जिसने हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को तकनीकी, सामरिक और सामुद्रिक नेतृत्व की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है।

अगले तीन फ्रिगेट 2026 तक नौसेना को मिल जाएंगे, जिससे भारत की समुद्री शक्ति दुनिया की प्रमुख नौ सेनाओं की श्रेणी में और ऊपर पहुंचेगी।

‘तारागिरी’ के डेक पर तिरंगा लहराते ही यह संदेश पूरे विश्व तक पहुंच गया—भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर है, बल्कि समुद्री सुरक्षा और आधुनिक रक्षा तकनीक के भविष्य को अपने हाथों से गढ़ने में सक्षम है।

यह क्षण सिर्फ नौसेना का नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का गौरव बन गया—समुद्र की लहरों पर गूंजता भारत का स्वाभिमान।

दिल्ली कार ब्लास्ट की जांच ने पकड़ी नई दिशा: विदेश से पढ़े डॉक्टरों की विस्तृत जानकारी तलब, राजधानी के अस्पतालों को कड़े नोटिस जारी

(जीएनएस)। नई दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था उस समय और अधिक सतर्क हो गई जब 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए कार बम विस्फोट ने जांच एजेंसियों को एक व्यापक नेटवर्क की ओर संकेत दिया। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, दिल्ली पुलिस ने एक असाधारण कदम उठाते हुए राजधानी के सभी निजी अस्पतालों को नोटिस भेजे हैं। इन नोटिसों में उन डॉक्टरों का पूरा विवरण मांगा गया है जिन्होंने एमबीबीएस की डिग्री विदेश से ली है, और वर्तमान में दिल्ली में चिकित्सा सेवा दे रहे हैं।

नोटिस में विशेष रूप से चार देशों—पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई और चीन—का उल्लेख किया गया है। पुलिस का कहना है कि यह कदम सीधे सुरक्षा कारणों से उठाया गया है, क्योंकि जांच के शुरुआती निष्कर्ष बताते हैं कि ब्लास्ट मॉड्यूल ने कई “डॉक्टर मॉड्यूल” सदस्यों की मदद से तकनीकी डेटा, चिकित्सा पहचान और सफर को छिपाने वाली जानकारी का दुरुपयोग किया।

दिल्ली पुलिस का मानना है कि शहर में काम कर रहे विदेशी-प्रशिक्षित डॉक्टरों की सटीक सूची और सत्यापन इस पूरी जांच में महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है। निजी अस्पतालों के प्रशासन के सामने यह साफ निर्देश रखा गया है कि वे अपने यहां काम कर रहे हर विदेशी-डिग्रीधारी चिकित्सक का ब्योरा—शैक्षणिक दस्तावेज, पासपोर्ट/वीजा विवरण, काम की अवधि और विभागों—समेत तुरंत जमा करें।

इसी बीच एनआईए ने बताया है कि देश के कई राज्यों में लगातार छापेमारी जारी है। अब तक सात मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि प्रमुख साजिशकर्ता उमर के छह सहयोगी पहले ही पकड़े जा चुके थे। जांच एजेंसियां यह समझने में जुटी हैं कि कैसे एक व्यापक सुसाइड बॉम्ब मॉड्यूल को तकनीकी और मानव संसाधन के स्तर पर संचालित किया जा रहा था—और इसमें कौन-कौन से पेशेवर लोग शामिल या उपयोग किए गए थे।

जांच के केंद्र में है दानिश—एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पढ़ाई राजनीति विज्ञान में थी, लेकिन जिसे आतंकी संगठन ने तकनीकी ज्ञान और आत्मघाती मिशन के लिए तैयार करने की कोशिश की। एनआईए ने यह खुलासा किया कि दानिश ने विस्फोट से पहले एक ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए और रॉकेट बनाने का प्रयास भी किया। उसे अक्टूबर 2024 में कुलगाम की मस्जिद में कथित “डॉक्टर मॉड्यूल” से मिलवाया गया, फिर फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कुछ दिनों तक रखा गया। यह पूरा नेटवर्क उसे जैश-ए-मोहम्मद के ओवर-ग्राउंड वर्कर के रूप में तैयार करना चाहता था, लेकिन अप्रैल 2025 में उसने आत्मघाती हमलावर बनने से इंकार कर दिया।

इन खुलासों के बीच पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को इस केस में चार डॉक्टरों की एनआईए हिरासत सात दिन और बढ़ा दी। इनमें पुलवामा के डॉ. मुजम्मिल शकील गनई, जम्मू-कश्मीर के डॉ. आदिल अहमद रतहर, लखनऊ के डॉ. शाहीन सईद और जम्मू-कश्मीर के मुफ्ती इरफान वागे शामिल हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह चारों आरोपी “डॉक्टर मॉड्यूल” की अहम कड़ियाँ हो सकते हैं—जो तकनीकी सहायता, पहचान छिपाने और भर्ती प्रक्रिया में भूमिका निभाते थे।

इसके पहले 27 नवंबर को आरोपित जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश की हिरासत भी सात दिन के लिए बढ़ाई गई थी। पूछताछ के दौरान वह कई संवेदनशील और जटिल जानकारियां दे चुका है, जिनकी तस्दीक और नेटवर्क ट्रेसिंग अभी जारी है।

लाल किले जैसे अत्यधिक सुरक्षित क्षेत्र में हुए इस धमाके ने देशभर की जांच एजेंसियों को हाई-अलर्ट पर ला दिया है। अब जांच सिर्फ एक विस्फोट तक सीमित नहीं रही—यह एक पूरे तंत्र, एक पूरे मॉड्यूल, और उन पेशेवरों तक पहुँचने का अभियान बन चुकी है, जिनकी विशेषज्ञता का दुरुपयोग कर एक बड़ा आतंकी नेटवर्क खड़ा किया गया था।

“चक्रवात ‘दित्वा’ ने श्रीलंका में मचाई तबाही, 69 की मौत, राहत और खोज अभियान जारी, भारत ने तुरंत भेजी मदद”

(जीएनएस)। कोलंबो। चक्रवाती तूफान दित्वा ने श्रीलंका में व्यापक जन–धन और जनजीवन की हानि पहुंचाई है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने कई जिलों में तबाही मचा दी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 69 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल उनकी तलाश में दिन-रात जुटे हुए हैं।

तूफान की शक्ति के कारण कई प्रमुख पुल, सड़कों और संपर्क मार्गों को गंभीर क्षति पहुंची है, जिससे दूर-दराज के इलाकों में आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने सभी बिजली, पेट्रोलियम, गैस, अस्पताल और जलापूर्ति से जुड़ी सेवाओं को आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में शामिल किया ताकि आपातकालीन राहत कार्य बिना बाधा चले। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि देश के ऊपर बना निम्न-दाब क्षेत्र अभी भी सक्रिय है, जिससे तेज हवाओं और भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।

विशेष रूप से मोरागहाकांडा जलाशय

की क्षमता भर जाने के बाद स्पिल गेट खोलने पड़े, जिससे मोरागहाकांडा–लग्गाला का महत्वपूर्ण पुल ढह गया। यह पुल मटाले, पोलोन्नारुवा और कुरुनेगला जिलों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी था और इसकी क्षति से राहत कार्यों में अतिरिक्त बाधा आई है। भूस्खलन और तेज बारिश के कारण हसलाका क्षेत्र में याहंगला पर्वत के पास पांच शव बरामद किए गए। श्रीलंका के आपदा प्रबंधन केंद्र (डीएमसी) के अनुसार, 16 नवंबर से अब तक इस आपदा ने 63,000 से अधिक परिवारों यानी 2.19 लाख लोगों को प्रभावित किया है। कई इलाकों में भूस्खलन का खतरा अभी भी बना हुआ है, और राहत कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति में चल रहे हैं। सरकार ने विदेशों में बसे श्रीलंकाई नागरिकों और अन्य देशों के लोगों से भी राहत कार्यों में सहयोग का आग्रह किया है। इसके लिए बैंक खाते का विवरण विदेश मिशनों में उपलब्ध कराया गया है, ताकि अंतरराष्ट्रीय सहयोग से राहत कार्य तेज़ी से आगे बढ़ सके।

इस बीच, भारत ने ‘ऑपरेशन सागर बंधु’ के तहत तुरंत राहत सामग्री भेजी है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बताया कि आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी द्वारा राहत सामग्री कोलंबो पहुंचा दी गई है और आगे भी आवश्यक मदद भेजी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत श्रीलंका के कठिन समय में खड़ा है और हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है।

चक्रवात ‘दित्वा’ ने श्रीलंका में न केवल मानवीय संकट पैदा किया है, बल्कि बुनियादी ढांचे और संपर्क मार्गों को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। राहत अभियान में सरकारी दलों के साथ-साथ स्वयंसेवी संगठन और पड़ोसी देशों की मदद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, ताकि तेज़ बारिश और भूस्खलन के बीच प्रभावित लोगों तक सुरक्षित सहायता पहुंचाई जा सके।

“समुद्री शक्ति का नया अध्याय: नौसेना बनेगी भविष्य की रणनीतिक धुरी, सीडीएस चौहान का प्रेरक संदेश”

(जीएनएस)। एझिमाला की पहाड़ियों पर फैली सुबह की हल्की धूप जब भारतीय नौसेना अकादमी के विशाल परिसर पर पड़ी, तो पूरा परेड मैदान अनुशासन, उत्साह और नई ऊर्जा से भर गया। इस गरिमामयी वातावरण के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल अनिल चौहान का आगमन हुआ, जिनके शब्दों ने न सिर्फ नव-नियुक्त अधिकारियों, बल्कि हर मौजूद व्यक्ति के भीतर गर्व और जिम्मेदारी की नई भावना पैदा की। जनरल चौहान ने अपने संवाद की शुरुआत एक ऐसे सत्य से की, जिसकी प्रतिध्वनि आज दुनिया की बदलती भू-राजनीति में स्पष्ट सुनाई देती है—भारत सिर्फ एक महाद्वीपीय शक्ति नहीं, बल्कि एक उभरती हुई समुद्री महाशक्ति है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आने वाले दशक देश की सुरक्षा, उसकी रणनीतिक दिशा और वैश्विक प्रभाव का बड़ा हिस्सा महासागरों में ही लिखा जाएगा। हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ते तनाव, तकनीकी दौड़ और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के इस दौर में नौसेना की भूमिका अब पहले से कहीं अधिक निर्णायक होने वाली है। अपने संबोधन में सीडीएस ने समुद्री सीमाओं की विशालता और चुनौतियों की जटिलता की ओर इशारा करते हुए बताया कि भारत की सुरक्षा अब सिर्फ जमीन पर लड़ाई तक सीमित नहीं है। समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, गहरे समुद्र में उभरते खतरे, साइबर-युद्ध का विस्तार, ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट आधारित निगरानी—ये सभी मिलकर भविष्य की सैन्य रणनीति को नया रूप दे रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि आधुनिक युद्ध भूगोल को पार कर चुका है; आज राष्ट्र की सुरक्षा उस तकनीक पर निर्भर है, जिसे संचालित करने की क्षमता सिर्फ दक्ष, प्रशिक्षित और समर्पित अधिकारियों में होती है।

उन्होंने नव-नियुक्त अधिकारियों को गूंजते हुए शब्दों में चेताया—“युद्ध के मैदान में अक्षमता की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। इसलिए प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई हर दक्षता को जीवनभर निखारना ही सच्चे सैनिक का धर्म है।”

उनके इन शब्दों से पूरा मैदान कुछ पल के लिए शांत हो गया, मानो हर अधिकारी अपने भीतर दृढ़ निश्चय का एक नया आयाम महसूस करने लगा हो।

जनरल चौहान ने तीनों सेनाओं के बीच संयुक्तता पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्ध किसी एक सेवा द्वारा नहीं लड़े जा सकते। यह वह समय है जब सेना, नौसेना और वायुसेना की क्षमताओं का एकीकरण ही भारत की सबसे बड़ी सामरिक शक्ति बनेगा। ऑपरेशनल स्तर पर एकजुटता ही भविष्य की जीत की कुंजी होगी।

इस वर्ष की परेड कई मायनों में खास रही। इसमें बांग्लादेश, मालदीव, मोजाम्बिक, म्यांमार, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम जैसे देशों के कैडेटों ने हिस्सा लेकर भारत की बढ़ती समुद्री साझेदारियों और क्षेत्रीय सहयोग का सशक्त संदेश दिया। यह सिर्फ एक परेड नहीं, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भरोसेमंद नेतृत्व भूमिका का प्रतीक था।

परेड मैदान में कदमों की धुन, तलवारों की चमक और नौसेना के गीतों की स्वर-लहरियां जब गूंजीं, तो उपस्थित अभिभावकों की आंखें गर्व से भर आईं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेटों को पदक और ट्रॉफियां प्रदान की गईं।

“व्हाइट हाउस हमले के बाद अमेरिका ने अफगान पासपोर्ट पर वीजा जारी करने पर लगाई रोक, सुरक्षा को बनाया सर्वोच्च प्राथमिकता”

(जीएनएस)। वॉशिंगटन। अमेरिकी प्रशासन ने हाल ही में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अफगान पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले सभी लोगों के लिए वीजा जारी करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह कदम 26 नवंबर को व्हाइट हाउस के पास हुई गोलीबारी की घटना के बाद उठाया गया, जिसमें एक अफगान नागरिक द्वारा दो सुरक्षा गार्डों को गोली मार दी गई थी।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि नई व्यवस्था के तहत अफगान पासपोर्ट धारकों को फिलहाल किसी भी श्रेणी का वीजा नहीं मिलेगा। विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर साझा किए गए संदेश में बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशों के अनुसार यह रोक लगाई गई है। रुबियो ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

राष्ट्रपति ट्रंप ने सुरक्षा के नाम पर कड़ा रुख अपनाते हुए संकेत दिया कि अमेरिका उन देशों के प्रवासियों पर विशेष ध्यान देगा, जिन्हें सुरक्षा जोखिम के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका में मौजूद गैर-नागरिकों को मिलने वाले संघीय लाभ और सब्सिडी पर भी रोक लगाई जाएगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय अमेरिका की आव्रजन नीति में बड़े बदलाव का संकेत है। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि इस कदम से संभावित आतंकी और जोखिम भरे तत्वों को समय रहते नियंत्रित किया जा सकेगा। वहीं, विभिन्न मानवीय और शरणार्थी संगठनों ने इस निर्णय को लेकर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि इससे हजारों अफगान नागरिकों की यात्रा, रोजगार और वीजा प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

अमेरिकी प्रशासन का यह कदम दिखाता है कि सुरक्षा की दृष्टि से वीजा नीतियों में कड़ाई की जा रही है, और भविष्य में यह नीति अफगान नागरिकों के लिए आव्रजन और स्थायी निवास संबंधी विकल्पों को सीमित कर सकती है। वहीं, यह फैसला उन अफगान नागरिकों के लिए चुनौती बन सकता है, जो अमेरिका में शिक्षा, रोजगार या शरण के अवसर तलाश रहे हैं।

इस तरह अमेरिका ने स्पष्ट संदेश दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता होगी, और विदेश नागरिकों की वीजा प्रक्रिया में संशोधन किए जा सकते हैं, खासकर ऐसे देशों के नागरिकों के लिए जहां सुरक्षा जोखिम अधिक माना जाता है।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

सात राज्यों की साझा पहल लाएगी रंग

आज सिर्फ पंजाब-हरियाणा ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी नशीले पदार्थों का बढ़ता घातक कारोबार गंभीर संकट की आहट सुना रहा है। आये दिन विभिन्न राज्यों में नशीले पदार्थों की बड़ी-बड़ी खेप बरामद होना इस संकट की भयावह तस्वीर उकेरता है। अब वयस्क ही नहीं, किशोर भी नशे की चपेट में आ रहे हैं। फिर वे अपने नशे के लिए पैसा जुटाने को अपराध की गलियों से गुजरने में गुरेज नहीं करते। हाल ही के कुछ गंभीर अपराधों का खुलासा होने पर किशोरों ने स्वीकार किया कि वे नशे हेतु पैसा जुटाने के लिए अपराध करने निकले थे। कमोबेश, ऐसा ही संकट नकली दवाइयों की आपूर्ति का भी है। पिछले दिनों देश के कई राज्यों में घातक कफ सिरप पीने से कई बच्चे अपनी जान गंवा बैठे। इस आसन्न संकट को महसूस करते हुए नकली दवाइयों और मादक पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए सात राज्यों के ड्रग्स कंट्रोलरों, पुलिस और सीआईडी अधिकारियों का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन चंडीगढ़ में आयोजित किया गया, जिसका मकसद इन अधिकारियों को एक मंच पर लाकर कार्रवाई को अधिक कारगर बनाना था। इस रणनीतिक महत्व के सेमिनार का आयोजन हरियाणा के खाद्य और औषधि प्रशासन ने किया था, जिसका मकसद सीमावर्ती राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, सूचना साझेदारी और तेज प्रवर्तन तंत्र विकसित करना था। यह स्वागत योग्य है कि देश में पहली बार सात राज्यों ने इस संकट को महसूस करते हुए इस दिशा में साझी पहल की। उल्लेखनीय है कि इस पहल में सीमावर्ती राज्यों पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड व दिल्ली, महाराष्ट्र तथा हरियाणा के औषधि नियंत्रकों व वरिष्ठ अधिकारियों समेत 70 अधिकारियों ने भाग लिया। इन अधिकारियों ने अनुभव साझा करके भविष्य के लिए कारगर रणनीति को अंजाम देने पर गंभीर मंथन किया। बैठक में स्वीकार किया गया कि नशीले पदार्थों व नकली दवाइयों का कारोबार मात्र एक राज्य की समस्या नहीं है, बल्कि इससे कई राष्ट्रीय मुद्दे भी जुड़े हैं।

इसमें दो राय नहीं कि देश के लिए घातक साबित हो रहे नशे के कारोबार पर अंकुश राज्यों के संयुक्त प्रयासों से ही संभव है। इसके लिए जरूरी है कि विभिन्न राज्यों के जिम्मेदार अधिकारी समय-समय पर इससे जुड़े डेटा साझा करने, पारदर्शी समन्वय और 'एक टीम, एक रणनीति' पर काम करें। साथ ही जरूरी है कि संबंधित अधिकारी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ काम करें। इस दौरान सात राज्यों के अधिकारियों ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग रोकने व नकली दवाइयों पर रोक लगाने के लिए सहयोग करने पर सहमति जतायी। इस नई चुनौती के मुकाबले के लिए विशेष प्रशिक्षण और सात राज्यों के ड्रग कंट्रोलरों और पुलिस अधिकारियों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान पर सहमति बनी। इसमें दो राय नहीं कि यह जहरीला कारोबार सिर्फ स्थानीय मुद्दा नहीं है बल्कि विभिन्न राज्यों के बीच साझा चुनौती बना हुआ है, जिसका मुकाबल डेटा साझेदारी और पारदर्शी समन्वय से ही संभव है। खासकर सीमावर्ती राज्यों को तो अंतर्राष्ट्रीय व अंतरराज्यीय तस्करों से मुकाबले के लिए मिलकर काम करना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि चंडीगढ़ में आयोजित सेमिनार के निष्कर्ष राज्य व केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया ताकि साझी रणनीति तय की जा सके। दरअसल, हाल के दिनों में पंजाब व देश के समुद्री सीमा से जुड़े राज्यों में नशीले पदार्थों की जो बड़ी खेपें बरामद हुई हैं, उसने पूरे देश की चिंता बढ़ाई है। सवाल यह भी उठा है कि यदि नशीले पदार्थों की इतनी बड़ी मात्रा बरामद हुई है तो चोरी-छिपे कितनी बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ देश में पहुंच रहा होगा। पंजाब के सीमावर्ती जिलों में सीमा पार से ड्रोन के जरिये लगातार नशीले पदार्थ व हथियार भेजने के मामले प्रकाश में आए हैं। संकट का एक पहलू यह भी है कि सीमावर्ती जिलों में किशोरों को नशे की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब सरकार के विशेष अभियान के दौरान भी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की बरामदगी हुई है। अनेक तस्कर व दोहरी भूमिका निभाने वाले पुलिस कर्मियों तक भी कानून के हाथ पहुंचे हैं। लेकिन अभी भी इस दिशा में बहुत किया जाना बाकी है।

एक इतिहास की धारणा को बल, एक भूगोल का इंतजार

> बंटवारे से पहले सिंध की ज्यादातर आबादी हिंदू थी। प्रचलित शब्दों में वहां के लोगों को सिंधी कहा जाता है। सिंध के बंटवारे को यहां के हिंदू समाज ने ना तो व्यवहारिक माना, और ना ही उचित। आज यह पाकिस्तान का तीसरा बड़ा प्रांत है, जिसका क्षेत्रफल एक लाख 40 हजार 914 वर्ग किलोमीटर है।

जुलाई 2001 का दूसरा हफ्ता था। राजधानी दिल्ली और आगरा में बड़ी हलचल थी। इस हलचल पर समूचे देश या यूं कहिए कि दक्षिण एशिया की विशेष निगाह थी। वजह थी, पंद्रह जुलाई से शुरू हो रही परवेज मुशर्रफ की भारत यात्रा। करगिल युद्ध के खलनायक तब तक पाकिस्तान का शासक हो चुका था। मुशर्रफ तानाशाह राष्ट्रपति बन चुके थे। करगिल का जख्म चूंकि अभी हरा था, लिहाजा मुशर्रफ की यात्रा उत्सुकता, उम्मीद और आशंका के दायरे में थी। जैसा कि ऐसी यात्राओं के दौरान होता है, कूटनीतिक तैयारियां भी खूब होती हैं। परवेज की यात्रा के ठीक पहले अपने चिर-परिचित अंदाज में पाकिस्तान ने कश्मीरी आत्मनिर्णय को लेकर कूटनीतिक दबाव बनाना शुरू कर दिया था। यात्रा के एक या दो दिनों पहले की बात है। दिल्ली में सिंधी समाज ने मुशर्रफ की यात्रा के मद्देनजर एक कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तत्कालीन उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के सामने पाकिस्तान की उस कोशिश का जिक्र किया गया तो भरे मंच से उन्होंने पाकिस्तान को चेता दिया था, 'अगर पाकिस्तान कश्मीर का सवाल उठाएगा तो भारत जवाबी रूप से सिंध के आत्मनिर्णय का सवाल उठाएगा।' इस वाकये का जिक्र इसलिए हो रहा है कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ठीक चौबीस साल बाद सार्वजनिक मंच से कहा है कि भविष्य में सिंध भारत का हिस्सा हो सकता है। भारत की सीमाओं के बदलने की उम्मीद तो देश का एक तबका काफी अरसे से कर रहा है। लेकिन उसका ध्यान सिंध की बजाय बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर ज्यादा रहा है। सिंध का सवाल अपेक्षाकृत कम चर्चित और कम ध्यातव्य रहा है। लेकिन यह बात चूंकि देश के रक्षा मंत्री ने कही है तो यह मामला गंभीर हो जाता है। हो सकता है कि यह राजनाथ सिंह का निजी विचार हो। लेकिन वे भारत की आधिकारिक शासक मोदी कैबिनेट के दूसरे नंबर के व्यक्ति

हैं। इसलिए उनके शब्द कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उन शब्दों का प्रभाव राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पड़ने स्वाभाविक है। बंटवारे से पहले सिंध की ज्यादातर आबादी हिंदू थी। प्रचलित शब्दों में वहां के लोगों को सिंधी कहा जाता है। सिंध के बंटवारे को यहां के हिंदू समाज ने ना तो व्यवहारिक माना, और ना ही उचित। आज यह पाकिस्तान का तीसरा बड़ा प्रांत है, जिसका क्षेत्रफल एक लाख 40 हजार 914 वर्ग किलोमीटर है। गुजरात के कच्छ का रण और राजस्थान का थार रेगिस्तान इसके पूर्व में स्थित है, जबकि दक्षिण में इसका पांव अरब सागर पखार रहा है। अरब सागर के ही किनारे स्थित कराची पाकिस्तान का आर्थिक केंद्र है, जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है।

दुनिया के चाहे जिस भी हिस्से में हिंदू समाज रहता है, अपने धार्मिक और संस्कार वाले कामों, पूजा-अर्चना आदि में सबसे पहले खुद को एक मंत्र से पवित्र करता है और अर्चना में जिस जल का उपयोग करता है, उसे वह एक मंत्र के जरिए पवित्र करता है। वह मंत्र है, "गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु"। जिसका अभिप्राय है कि गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी के जले से यह अर्चन कार्य करता हूं। इस मंत्र से स्पष्ट है कि भारतीय मनीषा और संस्कृति के लिए सदियों से गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती , नर्मदा, सिंधु और कावेरी नदियों को पवित्रतम नदियां रही हैं। उनका जल हमारी सभ्यता का वाहक रहा है, उनके जरिए हमारी संस्कृति और सभ्यता का विकास हुआ है। भारत की सप्त पवित्र नदियों में से एक सिंधु इसी सिंध प्रांत से होकर गुजरती है। इस लिहाज से देखें तो भारत भूमि के लिए सिंध का महत्व समझ में आता है। लालकृष्ण आडवाणी भी सिंध के वासी रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि उनकी पीढ़ी के सिंध के लोग भारत के विभाजन को स्वीकार नहीं कर पाए। राजनाथ सिंह ने अपने व्याख्यान में इस लेख का भी जिक्र किया है। आडवाणी अपने राजनीतिक उत्कर्ष के दिनों में सिंधु दर्शन यात्रा नाम से आयोजन करते रहे हैं। जिसका मकसद सिंधु के जरिए सिंध की माटी से बिछड़कर भारत आ गए लोगों को जोड़ना और उनकी स्मृतियों को जिंदा रखना रहा।

ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून के तहत भारत विभाजन की योजना लार्ड माउंटबेटन ने बनाई। उन्होंने इसका जिम्मा कानून के जानकार सिरिल रेडक्लिफ को दिया। रेडक्लिफ को भूगोल और संस्कृति की जानकारी नहीं थी। विभाजन करते वक्त उन्होंने भारतीय वास्तविकताओं का ध्यान नहीं रखा। संस्कृतियों की भी समझ नहीं थी। इसका असर विभाजन पर भी दिखा। रेडक्लिफ रेखा एक तरह से उनकी मूर्खताओं का प्रतीक बन गई। उनकी संस्कृतिहीन सोच की वजह से भारत को विभाजन के वक्त भयानक विभीषिका को झेलना पड़ा। कई जगह पर विभाजन अगर कृत्रिम लगता है तो उसकी वजह रेडक्लिफ की संस्कृति, भूगोल और जमीनी हालात की नासमझी है।

इसी वजह से सिंध से भी भारत में विलय के लिए क्षीण ही सही, आवाजें उठती रहीं है। भारत से पाकिस्तान गए मुसलमानों को भी सम्मान नहीं मिला. उन्हें बिहारी और मुहाजिर कहा जाता रहा। एक दौर में सिंध में मुहाजिर कौमी मूवमेंट चलता रहा, जिसके प्रमुख अल्ताफ हुसैन रहे। हालांकि उनके आंदोलन का मकसद पाकिस्तान में भारत से गए उर्दू भाषी मुसलमानों के अधिकारो की रक्षा रहा। लेकिन पाकिस्तान सरकार उसे भारत समर्थक और विभाजनकारी मानती रही।

बाल्टिस्तान, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर से तो भारत के साथ जुड़ने की मांग उठती रही है। हाल के दिनों में इस मांग ने तेजी पकड़ी है। वहां से आने वाले वीडियो में 'मोदी-मोदी ' के नारे भी सुनाई देने लगे हैं। हालांकि सिंध प्रांत से ऐसी आवाजें कम उठती रहीं। यहां याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान के एक प्रमुख राजनीतिक दल 'पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी' का सबसे ज्यादा असर सिंध प्रांत में ही है। जिसकी प्रमुख एक दौर में बेनजीर भुट्टो रही हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी भुट्टो परिवार की जागीर मानी जाती है।

इन संदर्भों में देखें तो राजनाथ सिंह के बयान इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि सिंध में विभाजन को लेकर मांग बढ़ रही है। पाकिस्तान की बदहाली, उर्दू भाषी मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे के व्यवहार की वजह से सिंध प्रांत में रह से मुहाजिर लोगों में भी भारत के प्रति अनुराग बढ़ रहा है। बेशक भारत से सीधी जुड़ी रही पीढ़ी अब नहीं रही, लेकिन उसने अपना दर्द, अपने सुहाने सपने और गौरवशाली अतीत को नई पीढ़ी के साथ साझा किया है। नई पीढ़ी के पास सूचना तकनीक है, सूचना के तमाम साधन है। इसलिए वह देख पा रही है कि सीमा के उस पार की हालत कैसी है। उसके लिए भारत का नजारा दर्द और क्षोभ का कारण बन जाता है। क्योंकि आजादी के पहले संयुक्त भारत में सिंध की गिनती समृद्ध राज्यों में होती थी। सिंध कभी हिंदू बहुल राज्य था। कराची शहर हिंदू प्रधान था। पाकिस्तान की जनसंख्या में सिर्फ 2.17 फीसद हिंदू हैं। जो करीब 52 लाख हैं। इनमें से करीब 49 लाख सिंध में ही रहते हैं। 2023 की जनगणना से अनुसार सिंध की आबादी करीब 5.57 करोड़ है। इस लिहाज से देखें तो यहां की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी करीब 8.8 प्रतिशत है। ग्रामीण आबादी में करीब 13.3 प्रतिशत हिंदू हैं. ये लोग ज्यादातर सिंध के थारपारकर और उमरकोट जिले में रहते हैं। विभाजन से पहले सिंध के कई जिलों में हिंदुओं की आबादी करीब 90 फीसद थी। 1941 की जनगणना के अनुसार, कराची में ही हिंदुओं की बड़ी संख्या में हिंदू आबादी थी। इसके अलावा शिकारपुर, खैरपुर, लरकाना, सुक्कुर में भारी संख्या में हिंदू रहते थे। आज भी उमरकोट जिले में मुस्लिम समुदाय की तुलना में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। इसकी दूरी भारतीय सीमा से सिर्फ 60 किलोमीटर है। कह सकते हैं कि राजनाथ सिंह के बयान ने वहां के हिंदू समुदाय के लोगों की उम्मीदें जगा दी होंगी। उन्हें लगता होगा कि एक न दिन वे भारत का उसी तरह हिस्सा होंगे, जैसे उनके पुरखे विभाजन के पहले थे। इस बयान ने एक अतीत और इतिहास की धारणा को जिंदा तो कर दिया है, एक भूगोल की उम्मीदें भी जगा दी हैं। एक भूगोल कब हकीकत बन पाएगा, यह कहना फिलहाल मुश्किल है।

प्रेरणा

जब एक सवाल ने खोल दिया अच्छाइयों का रहस्य

ईरान की शामें हमेशा से ही अपने भीतर एक अजीब-सी नरमी और सुकून लिए होती हैं—ठंडी हवा, दूर कहीं मस्जिद की धीमी अज़ान, और बाज़ारों से उठती हल्की मीठी खुशबू। ऐसी ही एक शाम, शेख़ सादी अपने घर के बाहर टहल रहे थे। उनका व्यक्तित्व वैसे भी इतना प्रभावशाली था कि लोग उन्हें देखते ही आदर में झुक जाया करते थे।

उसी समय एक नौजवान, जो कई दिनों से सादी की ख्याति और लोकप्रियता के बारे में सुन रहा था, हिम्मत जुटाकर उनके सामने आ गया। उसके चेहरे पर सम्मान भी था और एक बड़ी उलझन भी।

वह बोला, "हुज़ूर, लोग कहते हैं कि आपमें जितनी अच्छाइयाँ हैं, वह किसी और में नहीं। ढूँढ़ने पर भी कोई आपकी कोई कमी नहीं बता पाता। आखिर ये सारी अच्छाइयाँ आई कहाँ से? किसने आपको इतना श्रेष्ठ बना दिया?"

सादी ने उसकी ओर देखा। उनकी आँखों में किसी पहाड़ की तरह स्थिर गहराई थी। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा,

"बुरे लोगों से।"

यह उत्तर ऐसे लगा मानो किसी शांत कमरे में अचानक कोई दरवाज़ा जोर से बंद हो गया हो। नौजवान चौंक पड़ा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने सोचा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया।

"हुज़ूर क्या आपने सच में कहा कि आप अपनी

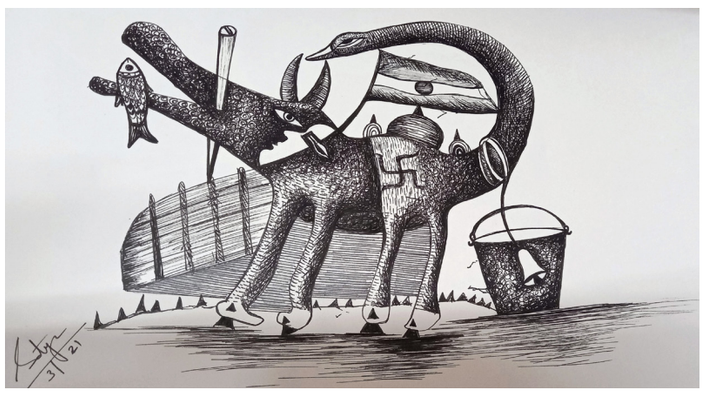

अच्छाइयाँ बुरे लोगों से सीखते हैं?"

सादी ने सिर हिलाया, फिर धीरे-धीरे कदम बढ़ाते हुए पास खड़े एक सूखे पेड़ की ओर गए। पेड़ बिल्कुल बेजान था—टहनियों से कांटे झूल रहे थे, और छाल भी खुरदरी हो चुकी थी।

उन्होंने पेड़ की ओर इशारा करके कहा,

"देखो, यह पेड़ किसी को छांव नहीं देता। इसके पास फल नहीं, फूल नहीं, सिर्फ़ कांटे हैं। लेकिन यही पेड़ मुझे यह सिखाता है कि मैं कैसा न बनूँ। दुनिया में जब मैंने किसी इंसान को टूटते देखा, गुस्से में दूसरों को चोट पहुंचाते देखा, झूठ बोलते, धोखा देते देखा—तो मैं हर बार सोचता था कि मैं ऐसा नहीं बनूँगा।"

फिर उन्होंने आगे कहा,

"कोई इंसान व्यर्थ नहीं होता। हर चेहरा एक किताब है।

कुछ किताबें हमें प्रेरणा देती हैं—और कुछ चेतावनी।

और चेतावनियाँ भी कम सीख नहीं होतीं।"

नौजवान अब ध्यान से सुन रहा था। उसके भीतर जैसे कोई नई खिड़की खुल रही थी।

सादी बोलते रहे,

"जब मैंने किसी को लालच में बर्बाद होते देखा, तो लालच से दूर हो गया।

जब मैंने किसी को झूठ बोलते देखा और उस झूठ का परिणाम देखा, तो मैंने दिल में पक्का कर लिया कि सच ही सबसे आसान साथी है।

जब मैंने किसी के भीतर घमंड देखा, जिसने उसे अपने ही लोगों से दूर कर दिया—मैंने तय किया कि विनम्र रहना ही सुंदर है।"

उन्होंने रुककर नौजवान की आँखों में देखा और बोले,

"अच्छाई कोई चमत्कार नहीं होती। अच्छाई एक चुनाव है।

हर दिन, हर पल—हम यह तय करते हैं कि हमें कौन-सा रास्ता चुनना है।

मेरी अच्छाइयों का राज बस इतना है कि दुनिया की हर बुराई को मैंने आईने की तरह देखा और उसमें अपनी कमियाँ ढूँढ़कर उन्हें बदलता गया।"

नौजवान अब बिल्कुल शांत खड़ा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह जीवन की किसी गहरी नदी के किनारे आ खड़ा हुआ है, जिसकी लहरें धीरे-धीरे उसके भीतर उतर रही हैं।

सादी ने अंत में बस इतना कहा,

"अगर तुम दुनिया को गुरू बनाकर देखोगे, तो तुम्हें हर बुरे में एक सीख मिलेगी

और हर सीख तुम्हें एक नया, बेहतर इंसान बनाएगी।"

वह रात लंबी थी, लेकिन नौजवान को लगा कि उसने वर्षों की बुद्धि आज एक ही शाम में पा ली है—

क्योंकि कभी-कभी अच्छाई का असली स्रोत बुराइयाँ ही होती हैं, अगर उन्हें समझने और उनसे बचने की नीयत हो।

यूएसए और चीन के बाद भारत एशिया की तीसरी प्रमुख सैन्य शक्ति बना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत अब यूएसए और चीन के बाद एशिया की तीसरी प्रमुख सैन्य शक्ति बन चुका है। यह पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए किसी सदमे की तरह है। वहीं उनके आका देश अमेरिका और चीन के लिए भी एक झटके की तरह है, क्योंकि आने वाले वर्षों में इन्हें भी बारी-बारी पूर्वक पीछे छोड़ेगा। यह बात मैं नहीं बल्कि एशियन पॉवर इंडेक्स 2025 के8 एक वार्षिक सूची बोल रही है जो एशिया में देशों की समग्र शक्ति को मापती है। गौरतलब है कि इसमें आर्थिक, सैन्य, कूटनीतिक प्रभाव आदि आठ कैटेगिरी में देशों के संसाधन और प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। इस सूची में भारत 40.0 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है और इसे "मेजर पावर" यानी प्रमुख शक्ति घोषित किया गया है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए यह पायदान हासिल किया है, जबकि टॉप पर संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे नंबर पर चीन हैं।

एपीआई के अनुसार, भारत की आर्थिक क्षमता, फ्यूचर रिसोर्सेज और राजनयिक प्रभाव में खासा सुधार हुआ है। भारत की सैन्य क्षमता में भी निरंतर सुधार के चलते उसकी क्षेत्रीय और ग्लोबल भूमिका मजबूत हुई है। वहीं, पाकिस्तान इस सूची में 16वें स्थान पर है और टॉप 10 में नहीं है। एशियाई पावर इंडेक्स लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है, जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 27 देशों को देखता है और उनकी शक्ति संरचना का आकलन करता है। यह इंडेक्स सिर्फ सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं है बल्कि कुल प्रभाव क्षमता को मापता है, जिसमें अर्थव्यवस्था, कूटनीति, रक्षा नेटवर्क, संस्कृति आदि शामिल हैं। लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2025 को मापने के लिए आठ मुख्य मापदंडों का उपयोग किया जाता है: सैन्य क्षमता, आर्थिक क्षमता, रक्षा नेटवर्क, कूटनीतिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, पुनःस्थापन क्षमता (रेजिलिएंस), भविष्य के संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संबंध। कुल मिलाकर इसमें 30 उप-माप और 131 संकेतक शामिल हैं, जो किसी देश की व्यापक प्रभाव क्षमता का आंकलन करते हैं। यह इंडेक्स केवल सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह देशों की असली ताकत को उनके क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव, पड़ोसी देशों के साथ उनके रिश्ते, तकनीकी और व्यापारिक शक्तियों, और उनके भविष्य के विकास की संभावनाओं के हिसाब से मापता है। इस इंडेक्स के अंतर्गत हर देश को 100 अंकों के पैमाने पर स्कोर दिया जाता है, जो यह दर्शाता है कि वे एशिया में कितना प्रभावशाली हैं। लोवी इंस्टीट्यूट इस सूचकांक को एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 27 देशों पर लागू करता है और यह वार्षिक रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित होता है। इस इंडेक्स के परिणाम से देशों के भू-राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव और उनकी क्षेत्रीय भूमिका का पता चलता है। एशियन पॉवर इंडेक्स (एपीआई) के आठ माप निम्नलिखित हैं: पहला, सैन्य क्षमता– इसमें देश की सैन्य ताकत, हथियार, सैन्य कर्मियों और रक्षा बजट को मापा जाता है। दूसरा, आर्थिक क्षमता– देश की आर्थिक स्थिति, जीडीपी, मुद्रा रिजर्व, और अन्य आर्थिक संसाधनों का आकलन। तीसरा, रक्षा नेटवर्क– क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सैन्य गठबंधनों और सहयोग को मापा जाता है। चतुर्थ, कूटनीतिक प्रभाव– अन्य देशों के साथ राजनयिक संबंध, द्विपक्षीय समझौते और वैश्विक मंच पर देश की भूमिका।पंचम, सांस्कृतिक प्रभाव– देश की संस्कृति, भाषा, मीडिया प्रसारण और अन्य सांस्कृतिक माध्यमों के प्रभाव को दिखाता है। षष्टम, पुनःस्थापन क्षमता– प्राकृतिक आपदाओं, आर्थिक संकटों आदि का सामना करने की देश की सामर्थ्य। सप्तम, भविष्य के संसाधन– शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुसंधान-प्रौद्योगिकी विकास और युवा आबादी की संभावना। अष्टम, अंतरराष्ट्रीय संबंध– देश की विदेश नीति, व्यापार साझेदार और वैश्विक संगठनों में उसकी भागीदारी।

वस्तुतः ये आठ माप 30 उप-मापों और 131 संकेतकों के जरिए विस्तृत रूप से मूल्यांकन किए जाते हैं, जिससे किसी देश की समग्र शक्ति का आंकलन होता है। पूरे इंडेक्स का स्कोर 100 अंकों के पैमाने पर दिया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि कोई देश एशिया में कितना प्रभावशाली है। एशियन पावर इंडेक्स के उपर्युक्त आठ मापों का भारत के कुल स्कोर पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। भारत की सैन्य क्षमता, आर्थिक क्षमता, कूटनीतिक प्रभाव, और भविष्य के संसाधन जैसे माप उसकी पूरी ताकत को बढ़ाते हैं, जिससे भारत को बेहतर कुल स्कोर मिलता है।

उदाहरण के लिए, भारत की आर्थिक प्रगति और कूटनीतिक नेटवर्क में सुधार से इसकी रैंकिंग में मजबूती आई है। वहीं, पुनःस्थापन क्षमता और सांस्कृतिक प्रभाव जैसे माप भी भारत के क्षेत्रीय प्रभाव और वैश्विक छवि को मजबूत बनाते हैं। हालांकि, कुछ चुनौतियां जैसे प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने की क्षमता और संसाधनों का प्रभावी उपयोग भारत के स्कोर को सीमित भी कर सकता है। कुल मिलाकर, ये आठ माप मिलकर भारत की समग्र शक्ति और क्षेत्रीय भूमिका का आंकलन करते हैं, जो इस इंडेक्स में भारत के तीसरे स्थान पर आने का कारण हैं। इसलिए भारत की कुल रैंकिंग इन सभी क्षेत्रों में उसके प्रदर्शन का समग्र प्रतिबिंब होती है।

भारत ने एशियन पावर इंडेक्स के आठ मापों में सबसे अधिक सुधार आर्थिक क्षमता के क्षेत्र में किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले दशक में वैश्विक औसत के मुकाबले लगभग 90% की वृद्धि दर्ज की है, जो अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे उल्लेखनीय प्रगति है। यह सुधार भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), निवेश, विनिर्माण, और सेवा क्षेत्र में तेज विकास की वजह से हुआ है। इस तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत ने भारत को एशिया में तीसरे स्थान पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सैन्य क्षमता और कूटनीतिक प्रभाव में भी भारत ने सकारात्मक सुधार दिखाया है, लेकिन आर्थिक प्रगति सबसे प्रमुख योगदानकर्ता रही है। वहीं, कुछ क्षेत्रों जैसे प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की पुनःस्थापन क्षमता में अभी भी सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। कुल मिलाकर, आर्थिक मापों में भारत का मजबूत प्रदर्शन उसकी समग्र शक्ति और एशिया में प्रभाव बढ़ाने में सबसे बड़ा कारण है।

अभियान

जब आस्था अग्नि को भी ठंडा कर देती है: खंडेराव मंदिर का चमत्कारी अग्नि मेला

भारत की भूमि पर ऐसी अनगिनत परंपराएँ हैं जो सदी दर सदी न सिर्फ़ जीवित रहती हैं, बल्कि हर पीढ़ी को नई श्रद्धा, नया विस्मय और नया विश्वास भी देती हैं। मध्य प्रदेश के सागर ज़िले से लगभग 65 किलोमीटर दूर स्थित देवरी नगर की एक परंपरा ऐसी ही है—जिसे देखने वाला हर व्यक्ति यही सोचता रह जाता है कि क्या सच में आस्था आग को भी जीत सकती है?

देवरी के प्राचीन श्री देव खंडेराव मंदिर में हर वर्ष अगहन माह की शुक्ल पक्ष की चंपा षष्ठी से पूर्णिमा तक अग्नि मेला लगता है। लगभग 400 वर्ष पुरानी यह परंपरा आज भी उतनी ही उत्साह, ऊर्जा और विश्वास से निभाई जाती है, जितनी शुरुआत में निभाई गई थी। यह वही परंपरा है जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु दहकते अंगारों के विशाल अग्निकुंड पर नंगे पैर चलते हैं, और कहते हैं कि भगवान की कृपा उन्हें एक पल को भी जलन महसूस नहीं होने देती।

हर वर्ष हजारों भक्त इस अद्भुत दृश्य को देखने आते हैं, लेकिन इस वर्ष का नज़ारा और भी असाधारण था—एक साथ लगभग 300 श्रद्धालु, अलग-अलग अग्निकुंडों

से निकलकर नौ कदम अग्नि पर चले। उनके कदमों के नीचे अंगारों की चटकती हुई आवाज़ थी, ऊपर हाथों में हल्दी, पीले वस्त्र, और वातावरण में "जय खंडेराव!" की गूँज।

कहानी लगभग चार सौ साल पुरानी है। देवरी के राजा यशवंत राव का एकमात्र पुत्र अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। राजवैद्य, दवा, पूजा, टोने—सब हो गया, लेकिन बच्चे की हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती ही गई। राजा के लिए यह समय किसी तूफ़ान से कम नहीं था।

एक रात राजा दुःख और बेचैनी में सोए और उसी रात उन्हें एक अलौकिक स्वप्न हुआ—

भगवान देव खंडेराव उनके सामने प्रकट हुए।

भगवान ने कहा,

"यदि तुम हल्दी का हाथी चढ़ाकर, सच्चे मन से प्रार्थना कर, मेरे अग्निकुंड से नंगे पैर गुजरोगे

तो तुम्हारा पुत्र सुखपूर्वक जीवित रहेगा। चिंता मत करो, मैं उसके साथ हूँ।"

राजा ने स्वप्न को दर्शन माना और अगले ही दिन मंदिर पहुँचे। पूरे विधि-विधान से पूजा की, हल्दी का हाथी चढ़ाया और अपनी सारी भय-संदेह को भस्म करते हुए दहकते अग्निकुंड पर नंगे पैर चल दिए।

कहते हैं कि लौटते ही राजा का बेटा चमत्कारिक रूप से ठीक होने लगा। उस दिन से शुरू हुआ यह अग्नि-संस्कार आज भी उसी शक्ति के साथ जीवित है।

क्यों चलते हैं भक्त अग्नि पर?

भक्त कहते हैं—

"मनोकामना पूरी हो जाए तो अग्नि पर चलकर हम भगवान का धन्यवाद करते हैं।"

नंगे पैर, हाथों में हल्दी, पीले वस्त्र, उत्साह और रोमांच में डूबे जयकारे धीरे-धीरे भक्त अग्निकुंड में उतरते हैं और ठीक नौ कदम चलते हैं।

नौ कदम क्यों?

क्योंकि यह भगवान खंडेराव के नौ रूपों की प्रतीकात्मक यात्रा मानी जाती है।

अंगारों की तपिश इतनी तीव्र होती है कि दूर खड़े लोगों के पैरों को भी गर्मी महसूस होती है, लेकिन भक्त कहते हैं कि अग्नि उन पर कोई प्रभाव नहीं डालती। यह विश्वास पीढ़ियों से चला आ रहा है कि जिस व्यक्ति का मन पूरी तरह श्रद्धा से भरा हो, उसे जलन बिल्कुल महसूस नहीं होती।

अग्नि मेला चंपा षष्ठी से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है।

सबसे अद्भुत दृश्य वह होता है जब ठीक दोपहर 12 बजे सूर्य की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग पर पड़ती है। यह क्षण शुभ संकेत माना जाता है कि भगवान ने इस वर्ष की अग्नि-यात्रा स्वीकार कर ली है।

इसके बाद अग्निकुंड की पूजा होती है। हल्दी छिड़की जाती है, मंत्र गूँजने लगते हैं और फिर भक्त अंगारों पर उतरते हैं। भीड़ सांसें रोके देखती है—प्रत्येक कदम श्रद्धा के चरम का संकेत होता है।

इस परंपरा को देखने वाले कई लोग कहते हैं कि यह सिर्फ़ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि मानव विश्वास की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है।

जब एक मन सच्ची आस्था से भर जाता है, तो वह आग को भी ठंडा कर देता है।

जिस भक्त के लिए यह यात्रा सिर्फ़ नौ कदमों की नहीं—जीवन के सबसे बड़े विश्वास की जीत बन जाती है।

खंडेराव मंदिर का यह अग्नि मेला सिर्फ़ एक समारोह नहीं, बल्कि यह घोषणा है कि

जब हृदय में विश्वास हो और आत्मा में समर्पण—तो अग्नि भी राह बन जाती है, बाधा नहीं।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

12वाँ चिंतन शिविर – 2025, धरमपुर का समापन समारोह

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का 'विकसित गुजरात@2047' के लिए 'अर्निंग वेल-लिविंग वेल' के दो स्तंभों पर आधारित विकास यात्रा को गति देने के लिए 'थिंकिंक वेल-डूइंग वेल' का भाव जगाने का आह्वान

मुख्यमंत्री का कुपोषण के विरुद्ध सामूहिक अभियान शुरू करने का संकल्प

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- गुजरात समग्र देश के लिए विकास का रोल मॉडल बना, इसका श्रेय हमारे सामूहिक चिंतन तथा लोगों का भला करने की इच्छाशक्ति को जाता है
- अधिकारी ऑनरशिप के साथ पूर्ण समर्पण, दायित्व एवं लोक हित की प्रतिबद्धता से कार्यरत रहें
- केवल फाइल वर्क से संतोष न मानते हुए नियमित फील्ड विजिट तथा वास्तविक समस्याओं का सूझ-बूझ से सामना करने की पहल वृत्ति कार्यक्षमता को अनेक गुना बढ़ाएगी

-: उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी :-

- चिंतन शिविर के विभिन्न विषयों पर गंभीरतापूर्वक चिंतन एवं मनन से सुदूरवर्ती मानव के कल्याण तथा राज्य की विकास यात्रा को गतिमान बनाने का मार्ग स्थापित करें
- चिंतन शिविर से कुछ नया सीखकर लोगों के कल्याण के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करें

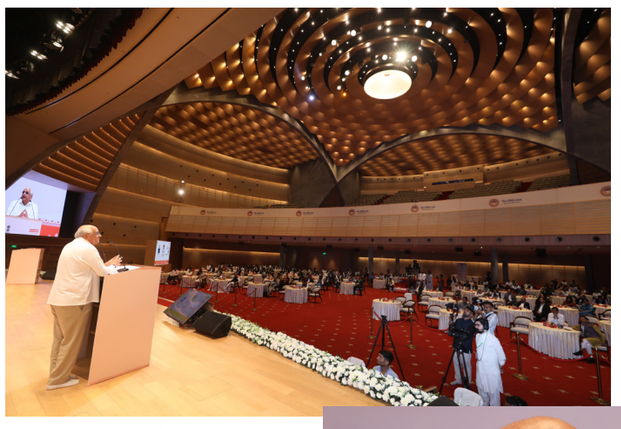

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों का आह्वान किया है कि वे सभी 'विकसित गुजरात@2047' के लिए 'अर्निंग वेल-लिविंग वेल' के दो स्तंभों पर आधारित विकास यात्रा को और गति देने के लिए 'थिंकिंग वेल-डूइंग वेल' का भाव जगाएँ।

श्री पटेल ने वलसाड जिले में धरमपुर स्थित श्रीमद् राजचंद्र आश्रम में 'सामूहिक चिंतन से सामूहिक विकास की ओर' थीम के साथ आयोजित 12वें चिंतन शिविर का शनिवार को समापन कराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए 'विकसित भारत@2047' के संकल्प में गुजरात को अग्रसर रखने का जो रोडमैप हमने लोगों के लिए 'अर्निंग वेल-लिविंग वेल' मंत्र के साथ तैयार किया है, उसे यह चिंतन शिविर 'थिंकिंग वेल-डूइंग वेल' के भाव से वैचारिक कलेवा प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अधिकारियों से कहा कि वे कर्तव्यों तथा विभागों की जिम्मेदारी ऑनरशिप, पूर्ण समर्पण, दायित्व एवं लोक हित की प्रतिबद्धता के साथ निभाएँ। उन्होंने कहा कि हम जहाँ हों, वहाँ अपना श्रेष्ठ कार्य निष्पादन देकर राज्य के विकास में आम आदमी के सुख-सुविधा के कार्यों में कार्यरत रहेंगे, तभी आत्मसंतोष मिलेगा।

उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि केवल फाइल वर्क करके संतोष न मानते हुए नियमित रूप से फील्ड विजिट, स्थल पर उपस्थिति, वास्तविक समस्याओं का सूझ-बूझ से सामना करने की पहल वृत्ति और लोक हित एवं कल्याण के लिए संवेदना जगाकर कार्यक्षमता में अनेक गुना वृद्धि हो सकती है और हमारे द्वारा किए गए कार्यों के मूल्यांकन से विकास की सच्ची दिशा निर्धारित हो सकती है।

श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2003 में अपने मुख्यमंत्रित्व काल में शुरू कराए गए चिंतन शिविर की उत्तरोत्तर सफलता में टीम गुजरात का परिश्रम और जन हित का सामूहिक चिंतन फलदायी रहा है। 2003 के प्रथम चिंतन शिविर में श्री मोदी ने प्रेरणा दी थी, "हमारा दृष्टिकोण एकीकृत हो, गाँवों को गरीबी से बाहर निकालें और एक भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे न रहे। आज जब भारत 21वीं शताब्दी की ओर अग्रसर है, तब इस शताब्दी को भारत की शताब्दी बनाने में हम सबकी ओर से कुछ योगदान होना चाहिए। यह केवल राजनीतिक या ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं है, बल्कि मानवजाति के उत्थान का एक छोटा प्रयास है।"

इस बात का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 'जो कहना, वह करना' का मंत्र अपनाया है और यह बात साकार करते हुए वे करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लेकर आए हैं तथा भारत तीसरी बड़ी आर्थिक महासत्ता बनने जा रहा है। गुजरात में हमने उनके दिशादर्शन में सर्वांगीण विकास की गति तेज बनाकर प्रतिव्यक्ति आय को पिछले ढाई दशक में 19823 रुपए से बढ़ाकर 3 लाख 22 हजार रुपए तक पहुँचाया है।

श्री पटेल ने तीन दिवसीय चिंतन शिविर के विभिन्न चर्चा सत्रों में हुए सामूहिक विचार-मंथन से मिले सुझावों पर वास्तविक क्रियान्वयन से सर्वांगीण विकास के लिए टीम स्पिरिट के साथ कार्यरत होने का मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कुपोषण के विरुद्ध सामूहिक अभियान शुरू करने का संकल्प व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने चिंतन शिविर में समूह चर्चाओं में आए विषयों पर हुए कामकाज के समय-समय पर मूल्यांकन और आगामी चिंतन शिविर में नई ऊर्जा तथा अधिक ऊँचे विकास लक्ष्यों के साथ मिलने की अपेक्षा व्यक्त की।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने चिंतन शिविर के विभिन्न विषयों पर गंभीरतापूर्वक चिंतन एवं मनन से सुदूरवर्ती मानव के कल्याण तथा राज्य की विकास यात्रा को गतिमान बनाने का मार्ग स्थापित करने का अनुरोध करते हुए कहा कि शिविर में हुई उदार मन से एवं पारदर्शी चर्चाएँ राज्य के विकास के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगी। यह जरूरी है कि तीन दिवसीय सामूहिक मनोमंथन से तैयार हुए मुद्दे केवल आर्काइव में ही न रहें, बल्कि उनका उचित डॉक्यमेंटेशन हो, जिसका सीधा लाभ गुजरात के आम नागरिकों को मिले।

श्री संघवी ने चिंतन शिविर से कुछ नया सीखकर लोगों के कल्याण के लिए जमीनी स्तर पर कार्यरत रहने का अनुरोध करते हुए कहा कि केवल सचिवालय स्तर पर ही नहीं, बल्कि ठेठ जिला प्रशासन तक शिविर की फलश्रुति पहुँचाएँ।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि श्रीमद् राजचंद्र आश्रम के आध्यात्मिक वातावरण में आयोजित हुआ चिंतन शिविर सभी नागरिकों के हित और किसी गरीब के आँसू पोंछने का संवेदनापूर्ण माध्यम बनेगा। उन्होंने शिविर के आयोजन में सहयोग देने के लिए राजचंद्र मिशन का आभार व्यक्त किया।

तीन दिवसीय चिंतन शिविर के समापन अवसर पर राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया, वरिष्ठ सचिव, जिला कलेक्टर, जिला विकास अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण प्रभाग के सचिव श्री हारित शुक्ला ने इस शिविर की सफलता के लिए सभी का आभार व्यक्त किया।

चिंतन शिविर – 2025 समापन

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के श्रेष्ठ जिला कलेक्टरों तथा जिला विकास अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किए

वर्ष 2024-2025 दौरान की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 4 आईआईएस अधिकारियों का "कर्मयोगी पुरस्कार" से सम्मान

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने धरमपुर स्थित श्रीमद राजचंद्र आश्रम में आयजित तीन दिवसीय 12वें चिंतन शिविर के शनिवार को समापन दिवस पर वर्ष 2024 से 2025 के दौरान उत्कृष्ट प्रशासनिक सेवाओं के लिए 4 आईआईएस अधिकारियों को कर्मयोगी पुरस्कार प्रदान किए।

मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में ये पुरस्कार दिए। जिन आईआईएस अधिकारियों को यह कर्मयोगी सम्मान मिला है, उनमें वलसाड के तत्कालीन जिला कलेक्टर श्री नैमेष दवे, पाटण के तत्कालीन जिला कलेक्टर श्री अरविंद वी., मोरबी के तत्कालीन जिला विकास अधिकारी श्री जे. एस. प्रजापति और आणंद के तत्कालीन जिला विकास अधिकारी श्री मिलिंद बापना शामिल हैं।

इस पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कृत को 51 हजार रुपए का नकद पुरस्कार और वे हाल में जिस जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हों, उस जिले के विकास के लिए 40 लाख रुपए का प्रोत्साहक अनुदान दिया गया।

प्रशासन में आधुनिक उपकरणों का उपयोग, नवीनतम योजनाओं-कार्यक्रम और अन्य मानदंडों को ध्यान में रखकर सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत समाविष्ट किए गए 'की परफॉर्मेंस इंडिकेटर' (केपीआई) के आधार पर राज्य के प्रशासन में गतिशीलता लाने एवं सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले जिला कलेक्टरों और जिला विकास अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2005 से जिला कलेक्टरों/जिला विकास अधिकारियों को कर्मयोगी पुरस्कार देने की योजना शुरू की गई है।

इस योजना के अंतर्गत जिला कलेक्टरों के लिए 81 केपीआई तथा जिला विकास अधिकारियों के लिए 73 केपीआई तय किए गए हैं। इस योजना में श्रेष्ठ जिला कलेक्टर/श्रेष्ठ जिला विकास अधिकारी के लिए कुल 100 गुण में से विभागों तथा मुख्य सचिव द्वारा उनकी कार्यक्षमता के मूल्यांकन के आधार पर राज्य सरकार को जो भी सिफारिशें की जाती हैं, उनके आधार पर ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस योजना अंतर्गत दो श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें एक; 15 लाख से अधिक जनसंख्या और महानगर पालिका क्षेत्र वाले जिले तथा दूसरी; 15 लाख तक की जनसंख्या वाले जिले।

12वें चिंतन शिविर के समापन दिवस पर प्रत्येक श्रेणी में दो कलेक्टरों और दो जिला विकास अधिकारियों सहित कुल मिलाकर चार आईआईएस अधिकारियों को वर्ष 2024-25 के लिए पुरस्कार दिए गए।

"भारत पर छाया नया आतंकी साया: आईएसआई की चालें तेज, इंडियन मुजाहिदीन को फिर जिंदा करने की साज़िश"

(जीएनएस)। नई दिल्ली की सर्द सुबहों में जब आम लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, उसी समय सुरक्षा एजेंसियों की टेबलों पर रखी फाइलों में एक नई चिंता आकार ले रही थी। राजधानी में लाल किले के पास हाल ही में हुई रहस्यमयी विस्फोट की घटना ने इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) को गहरे स्तर पर झकझोर दिया है। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी—यह संकेत था कि कहीं बाहर, भारत की स्थिरता और शांति के खिलाफ पुराने भटके हुए हाथ फिर से सक्रिय होने लगे हैं। आईबी के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब नई रणनीति के साथ भारत में आतंकी नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रही है। बीते वर्षों में कई बड़े आतंकी ढांचे ध्वस्त किए गए, कई मॉड्यूल पकड़े गए, और कई संगठन प्रतिबंधित हुए। लेकिन आतंकवाद की दुनिया कभी खाली जगह को खाली नहीं रहने देती—उसे भरने की कोशिशें लगातार जारी रहती हैं। यही कोशिश अब इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) को नए स्वरूप में पुनर्जीवित करने की दिखाई दे रही है। यह कहानी नए नहीं, पुराने किरदारों के साथ आगे बढ़ रही है। सिमी पर प्रतिबंध लगने के बाद रियाज और इक़बाल भटकल पाकिस्तान जाकर ऐसे छिप गए जैसे बादल पहाड़ों के पीछे। वहीं से उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन की नींव रखी थी। अब आईएसआई, इन भटकल बंधुओं को एक नए मॉडल, नए नाम और नई संरचना के साथ फिर से भारत में झोंकने की कोशिश कर रही है। आईएम के कई चेहरे आज भी कानून के शिकंजे से बाहर हैं, और कई राज्यों में उसका पुराना नेटवर्क नींद में पड़ा हुआ है, जिसे अब जगाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल गुजरात वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (जीसीसीआई) के वार्षिक स्नेहमिलन में उपस्थित रहे

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- कॉमनवेल्थ गेम्स-2030 की मेजबानी अहमदाबाद और गुजरात के लिए विकास के नए द्वार खोलेगी
- विकसित भारत@1947 के प्रधानमंत्री के सपने में गुजरात नए चिह्न अंकित करेगा
- वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट जैसे आयोजनों से स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा
- प्रधानमंत्री के प्रयासों से आज चिप से लेकर शिप तक के उद्योगों के कारण गुजरात सही अर्थ में देश का ग्रोथ इंजन बना

- उद्योग एवं अध्यात्म के समन्वय से भारत विकसित राष्ट्र तथा विश्वगुरु बनेगा : पू. ज्ञानवत्सल स्वामी

- मुख्यमंत्री के करकमलों से जीसीसीआई एन्युअल ट्रेड एक्सपो के द्वितीय संस्करण गेट-2026 के लोगो का अनावरण किया गया

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को अहमदाबाद में आयोजित गुजरात वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (जीसीसीआई) के वार्षिक स्नेहमिलन अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व तथा गृह मंत्री श्री अमित शाह के प्रयासों से अहमदाबाद को कॉमनवेल्थ गेम्स-2030 की मेजबानी मिली है, जो अहमदाबाद में विकास के नए बेंचमार्क सेट करेगी। इतना ही नहीं; इससे वर्ष 2036 में गुजरात में ओलंपिक खेलों के आयोजन के द्वार भी खुले हैं।

श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री की कार्यशक्ति के फल गुजरात को सदा-सर्वदा मिलते रहे हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने हर क्षेत्र की क्षमता पहचान कर राज्य में व्यापार-उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण, आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित ढाँचागत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की थी, जिसके परिणामस्वरूप गुजरात आज देश का ग्रोथ इंजन बना है।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2035 में गुजरात@75 की चर्चा करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के दिखाए मार्ग पर चलकर विकसित भारत@2047 के प्रधानमंत्री के सपने में गुजरात नए चिह्न अंकित करेगा ही।

राज्य की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए श्री पटेल ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य में हर क्षेत्र के विकास की नींव डाली थी, जिसके कारण आज गुजरात में चिप से लेकर शिप तक का उत्पादन हो रहा है। सबको साथ रखकर राज्य को विकास के मार्ग पर अग्रसर रखने के लिए प्रधानमंत्री के 'वोकल फॉर लोकल' तथा 'लोकल फॉर ग्लोबल' मंत्र का अनुकरण राज्य में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट का प्रारंभ किया गया है।

मुख्यमंत्री ने विकसित भारत के निर्माण में जीसीसीआई सहित व्यापार-उद्योगों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण के लिए राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने में सभी से स्वदेशी का मंत्र अपना कर अपना योगदान देने का अनुरोध किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के करकमलों से जीसीसीआई द्वारा वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले जीसीसीआई एन्युअल ट्रेड एक्सपो के द्वितीय संस्करण गेट (जीएटीई)-2026 के लोगो का अनावरण तथा पू. ज्ञानवत्सल स्वामी लिखित पुस्तक का विमोचन भी किया गया। स्नेहमिलन में उपस्थित बोचासणवासी अक्षर पुरुषोत्तम संस्था (बीएपीएस) के डॉ. ज्ञानवत्सल स्वामी ने इस सम्मेलन को उद्योग एवं अध्यात्म का समन्वय बताया। उन्होंने जी-20 समिट तथा दूसरे दिन राम मंदिर पर ध्वजारोहण के दोनों प्रसंगों में प्रधानमंत्री की उपस्थिति की तुलना विकास तथा भारत के विश्वगुरु बनने की दो समानांतर चलने वाली प्रक्रिया के साथ की। उन्होंने समाज में स्थिरता तथा गुणी व्यक्तियों के निर्माण के लिए उद्योग एवं अध्यात्म के समन्वय पर बल दिया।

इस अवसर पर जीसीसीआई के अध्यक्ष श्री संदीपभाई इंजीनियर ने वर्ष 2030 में आयोजित होने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी अहमदाबाद-गुजरात को मिलने पर मुख्यमत्री सहित समग्र टीम गुजरात को अभिनंदन दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रधानमत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में जीसीसीआई हर संभव सहयोग देगा। उन्होंने इसके लिए जीसीसीआई द्वारा आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का विवरण दिया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज राज्य में बिजनेस फ्रेंड्ली वातावरण का निर्माण हुआ है। उन्होंने व्यापारिक इकाइयों से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निवारण व सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर जीसीसीआई द्वारा आगामी वर्ष आयोजित होने वाले जीसीसीआई एन्युअल ट्रेड एक्सपो-गेट के द्वितीय संस्करण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल रिसाइकलिंग एक्सपो-ग्रीन्स तथा फार्म टु फैशन एवं ग्रेजर फेस्ट के बारे में और आयोजन की जानकारी वीडियो फिल्म के माध्यम से दी गई।

इस कार्यक्रम में अहमदाबाद की महापौर श्रीमती प्रतिभाबेन जैन, स्थानीय विधायकगण, जीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष श्री अजयभाई पटेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राजेशभाई गांधी, पदाधिकारी, विभिन्न समितियों के अध्यक्ष तथा जीसीसीआई के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

रेल राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह ने विकसित भारत के सपने को पूरा करने में भारतीय रेल एवं गतिशक्ति विश्वविद्यालय के योगदान को महत्वपूर्ण बताया

(जीएनएस)। माननीय रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह ने आज वडोदरा स्थित गतिशक्ति विश्वविद्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कांफ्रेंस हॉल में गतिशक्ति विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों एवं वडोदरा मंडल के अधिकारिओं को सम्बोधित किया। श्री रवनीत सिंह ने गतिशक्ति विश्वविद्यालय की टीम एवं वडोदरा मंडल के अधिकारिओं से माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान, समर्पण और प्रतिबद्धता का आवाहन किया। उन्होंने वडोदरा मंडल की उपलब्धियों की सराहना करते हुए इसे बेस्ट डिवीज़न बताया।

इस बैठक में गतिशक्ति विश्वविद्यालय के वाईस चांसलर प्रोफेसर मनोज चौधरी ने माननीय रेल राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह को प्रेजेंटेशन के माध्यम से गतिशक्ति विश्वविद्यालय की प्रगति और अचीवमेंट की जानकारी दी। प्रोफेसर चौधरी ने माननीय राज्य मंत्री को बताया कि परिवहन एवं लॉजिस्टिक क्षेत्र में भारत का अग्रणी विश्वविद्यालय, गति शक्ति विश्वविद्यालय (जीएसवी), 2022 में संसद के अधिनियम द्वारा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। रेल मंत्रालय (भारत सरकार) के अधीन कार्यरत, यह विश्वविद्यालय रेलवे, राजमार्ग, बंदरगाह, विमानन, समुद्री, नौवहन, अंतर्देशीय जलमार्ग, शहरी परिवहन और संपूर्ण रसद एवं आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क सहित संपूर्ण परिवहन क्षेत्र को कवर करता है। विश्वविद्यालय के चांसलर श्री अश्विनी वैष्णव (केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री) हैं। प्रोफेसर चौधरी ने आगे बताया कि हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सफ्रान ने विमानन और एमआरओ क्षेत्र के लिए इंडस्ट्री रेडी पेशेवरों को तैयार करने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय (जीएसवी) के साथ अपने सहयोग की घोषणा की। इस MOU के माध्यम से, जीएसवी ने अपने विमानन इंजीनियरिंग कार्यक्रम में विशेष लीप इंजन पाठ्यक्रमों को एकीकृत किया है, जिससे छात्रों को अत्याधुनिक एयरोइंजन प्रौद्योगिकियों का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा। उन्होंने गतिशक्ति विश्वविद्यालय की प्रगति की जानकारी देते हुए यह भी बताया कि एयरबस और GSV सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए जॉइंट स्टडी करेंगे। वडोदरा मंडल के रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने माननीय रेल राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह को प्रेजेंटेशन के माध्यम से वडोदरा मंडल की प्रगति और उपलब्धियों की जानकारी दी। श्री भडके ने पैसेंजर रिवेन्यू , टिकट चेकिंग आदि में मंडल द्वारा अर्जित गए नए कीर्तिमान, मंडल में लोडिंग के नए ट्रैफिक, गैर किराया राजस्व के जरिये यात्री सुविधाओं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत सामाजिक संघटनों एवं गैर सरकारी संघटनों द्वारा उपलब्ध कराई गयी यात्री सुविधाओं आदि की जानकारी दी।

श्री भडके ने दिवाली और छठ पर यात्री सुविधाओं के लिया मंडल द्वारा किये गए क्राउड मैनेजमेंट एवं M-UTS जैसे अन्य विशेष प्रयासों तथा जनप्रतिनिधियों के मांग पर मंडल द्वारा शुरु की गयी नयी ट्रेनों एवं विभिन्न स्टेशनों के अतिरिक्त स्टॉपेज की भी जानकारी दी। उन्होंने माननीय रेल राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत मंडल के स्टेशनों पर चल रहे कार्यों एवं मंडल पर चल रही विकास परियोजनाओं से भी अवगत कराया।

इस बैठक में गतिशक्ति विश्वविद्यालय के वाईस चांसलर श्री मनोज चौधरी सहित संकाय सदस्यों, वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके सहित मंडल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

"नक्सल मोर्चे पर बड़ी दरार: एमएमसी समिति के 11 इनामी नक्सलियों ने हथियार डाले, संगठन में मची हलचल"

(जीएनएस)। गोंदिया की धरती ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण मोड़ देखा—वो मोड़, जिस पर हिंसा की अंधेरी राह छोड़कर 11 कुख्यात और इनामी नक्सलियों ने मुख्यधारा की ओर कदम बढ़ाया। ये वही नक्सली थे, जिनके नाम सुनकर कभी पुलिस दस्ते सतर्क हो जाते थे, गांव के लोग सिहर उठते थे और जिनकी तलाश में कई राज्यों की सुरक्षा एजेंसियां महीनों तक जंगलों की खाक छानती रहती थीं। लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई थी। हथियारों से भरी वो मुट्ठियाँ अब आत्मसमर्पण के संकेत में खुल रही थीं।

महाराष्ट्र–मध्यप्रदेश–छत्तीसगढ़ (एमएमसी) विशेष प्रादेशिक समिति के ये सदस्य वर्षों तक जंगलों में सक्रिय रहे। इन पर महाराष्ट्र सरकार ने कुल 89 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था—जिसमें सिर्फ एक नाम सबसे ऊपर थाः अनंत उर्फ़ विकास नागपुरे उर्फ नवज्योत, जो संगठन की स्पेशल जोनल कमेटी का प्रमुख चेहरा था और जिसके सिर पर अकेले 25 लाख रुपये का इनाम रखा गया था। अनंत का आत्मसमर्पण न सिर्फ बड़ा झटका है, बल्कि यह संकेत भी कि नक्सल संगठन की आंतरिक संरचना तेज़ी से ढह रही है।

सुरक्षा अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करते समय इन नक्सलियों ने सात हथियार और पर्याप्त मात्रा में गोला-बारूद सौंपा। डीआईजी अंकित गोयल के अनुसार यह घटनाक्रम सिर्फ पुलिस की रणनीति का परिणाम नहीं, बल्कि "समन्वित पुलिसिंग और विश्वास बहाली कार्यक्रमों की सफलता" का प्रमाण है। हाल के महीनों में पुलिस और स्थानीय प्रशासन की 'पहुंच' नीतियों ने कई गांवों, आदिवासी क्षेत्रों और नक्सली प्रभावित इलाकों में विश्वास का नया पुल बनाया है।

आत्मसमर्पण की कहानी और पृष्ठभूमि

एमएमसी समिति के प्रवक्ता अनंत ने 27 नवंबर को ही प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी कि पूरी समिति 1 जनवरी 2026 तक सामूहिक आत्मसमर्पण करेगी। यह घोषणा नक्सल आंदोलन में अभूतपूर्व थी, क्योंकि इससे पहले कभी इतने बड़े स्तर पर सामूहिक आत्मसमर्पण की सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई थी।

लेकिन शुक्रवार की घटना इस घोषणा से भी आगे निकल गई—समिति के 11 सदस्य निर्धारित तारीख से काफी पहले ही हथियार छोड़ने आ गए। सुरक्षा विशेषज्ञ इसे दो कारणों से जोड़कर देखते हैंः

1. बीते एक वर्ष में सुरक्षा बलों की बढ़ी सक्रियता, जिसके दौरान आंदोलन के कई वरिष्ठ नेता मुठभेड़ों में मारे गए।
2. भूपति और चंद्रन्ना जैसे शीर्ष नेताओं के आत्मसमर्पण, जिन्होंने बाकी कैडरों के मन से डर की दीवार गिरा दी।

अनंत का संदेश भी काफी स्पष्ट था—"01 जनवरी तक कोई हिंसा नहीं होगी, और सभी प्रक्रियाएँ पूरी की जाएंगी।" इसका मतलब यह है कि संगठन के भीतर एक संवाद चल रहा है और उनका झुकाव आत्मसमर्पण की ओर बढ़ रहा है।

सालों से दंडकारण्य क्षेत्र नक्सल आंदोलन का कोर रहा है। इसी ढांचे की दूसरी शाखा, एमएमसी समिति, बेहद प्रभावशाली मानी जाती है। कभी मिलिंद तेलतुंबडे जैसे चर्चित नेता इसे दिशा देते थे। अब इसका नेतृत्व केंद्रीय समिति सदस्य रामधेर के पास है।

लेकिन 11 वरिष्ठ और इनामी नक्सलियों के एक साथ आत्मसमर्पण ने न सिर्फ एमएमसी के ढांचे में भारी कमज़ोरी पैदा की है, बल्कि आने वाले महीनों में और बड़े कदमों का संकेत भी दे दिया है।

आत्मसमर्पणकर्ताओं ने एक दिलचस्प शर्त भी रखी है—वे अंतिम और औपचारिक आत्मसमर्पण महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश या छत्तीसगढ़ के किसी एक मुख्यमंत्री के सामने करना चाहते हैं। उनके अनुसार यह सार्वजनिक और सम्मानजनक मंच उन्हें और अधिक लोगों को मुख्यधारा में आने के लिए प्रेरित करेगा।

मसूरी में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह: 'ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि जब प्रशासन और सेना एकजुट हों, तो देश अजेय हो जाता है'

(जीएनएस)। मसूरी की शांत, ठंडी हवा उस सुबह कुछ और महसूस करा रही थी। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी—जिसने भारत के प्रशासनिक इतिहास को दशकों तक आकार दिया है—आज 100वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह की गूंज से भरी हुई थी। इसी माहौल में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और उनका संबोधन ऐसा था, जिसने हर युवा प्रशिक्षु में देश के प्रति समर्पण, ईमानदारी और ज़िम्मेदारी की नई आग जगा दी।

राजनाथ सिंह ने अपने भाषण की शुरुआत उस ऑपरेशन से की जिसे उन्होंने "नागरिक-सैन्य समन्वय का सबसे उज्ज्वल उदाहरण" कहा—ऑपरेशन सिंदूर। उन्होंने बताया कि यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि देश के प्रशासन, सुरक्षा तंत्र और जनता के बीच विश्वास और धैर्य की एक अनोखी कहानी थी। प्रशासनिक अधिकारियों ने सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया, सूचनाएं साझा कीं, और देश भर में मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को समझाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा में उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है।

उन्होंने स्पष्ट कहा—

"हमारे सैनिकों ने संयम रखते हुए आतंकियों के ठिकाने नष्ट किए, लेकिन सीमा पर अस्थिरता का कारण पाकिस्तान का व्यवहार ही रहा। फिर भी, सेना और प्रशासन ने मिलकर यह दिखाया कि भारत किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम है।"

इसके बाद रक्षा मंत्री की नज़र उन युवा अफसरों पर गई जो पहली बार अपने करियर में एक नए मोड़ पर खड़े थे। उन्होंने कहा कि उन्हें न सिर्फ प्रशासक बनना है, बल्कि आदर्श, ईमानदार और जन-केंद्रित सेवक भी बनना है।

"सिर्फ नीति बनाना ही पर्याप्त नहीं, चरित्र भी वैसा होना चाहिए

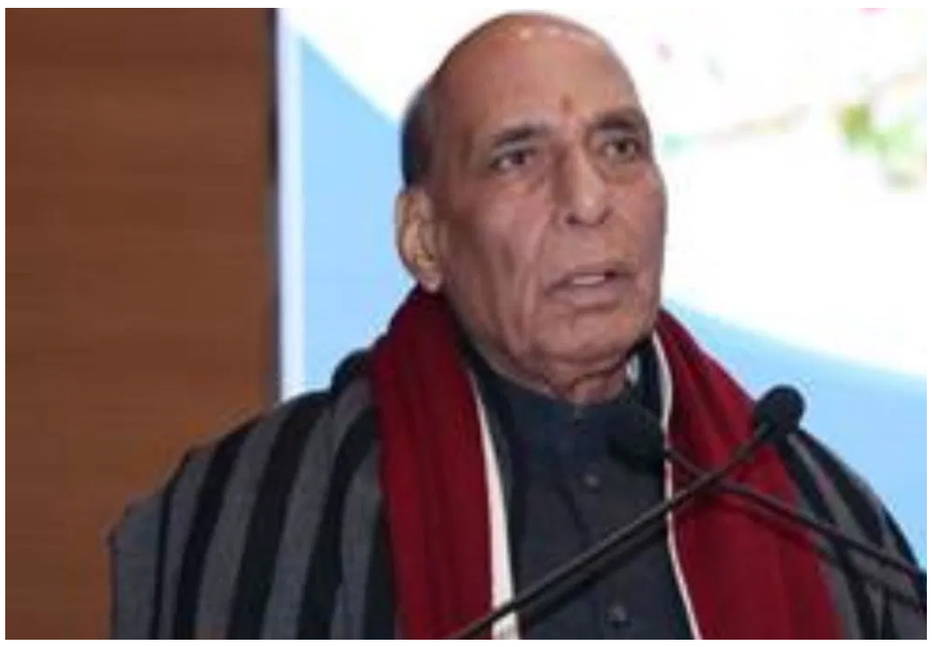

कि जनता को आप पर भरोसा हो। सत्यनिष्ठा कोई गुण नहीं, बल्कि रोज़मर्रा का नियम बननी चाहिए।"

फिर बात भारत के भविष्य की ओर मुड़ी। उन्होंने बताया कि 2014 में भारत आर्थिक रूप से 11वें स्थान पर था, जबकि आज वह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि यदि व्यवस्था पारदर्शी रहे और शासन में तकनीक का विवेकपूर्ण उपयोग हो, तो 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने में अब कोई संदेह नहीं रहेगा। मॉर्गन स्टेनली जैसी संस्था द्वारा भारत को जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताते हुए उन्होंने गर्व से कहा कि इस यात्रा में नागरिक सेवकों की भूमिका निर्णायक होगी।

उन्होंने तकनीकी अभियानों की चर्चा की—जन धन योजना से लेकर आयकर विभाग की फेसलेस असेसमेंट प्रणाली तक—और बताया कि टेक्नोलॉजी केवल उपकरण है, उसका उपयोग लोगों की समस्याओं को कम करने, पारदर्शिता बढ़ाने और कल्याणकारी योजनाओं को सशक्त बनाने के लिए होना चाहिए।

राजनाथ सिंह ने यह भी याद दिलाया कि एक प्रशासक सिर्फ आदेश देने वाला अधिकारी नहीं, बल्कि जनता के दुख-सुख को समझने वाला संवेदनशील साथी होना चाहिए।

"जब आप वंचित वर्ग से मिलें, तो याद रखें कि उनकी परिस्थितियां उनके प्रयासों से ज्यादा सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं से प्रभावित होती हैं।"

उन्होंने सिविल सेवाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि नवीनतम यूपीएससी परीक्षा में टॉपर एक महिला रही और शीर्ष पाँच में से तीन उम्मीदवार महिलाएं थीं।

"विश्वास है कि 2047 तक कई महिला अधिकारी कैबिनेट सचिव के पद तक पहुंचेंगी।" अपने संबोधन के अंत में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का उल्लेख किया—जिनके नाम पर यह अकादमी है। उन्होंने कहा कि शास्त्रीजी की सरलता, साहस, सत्यनिष्ठा और नेतृत्व आज भी हर प्रशासक के लिए आदर्श हैं। जय जवान, जय किसान का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1965 में था। समारोह से पहले राजनाथ सिंह ने शास्त्रीजी और सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की और परिसर में ओडीओपी मंडप का उद्घाटन किया। यह दृश्य देश की प्रशासनिक विरासत और उसके उज्ज्वल भविष्य के संगम जैसा प्रतीत हो रहा था।

मसूरी की उस सुबह ने न सिर्फ नए अफसरों को प्रेरित किया, बल्कि यह भी याद दिलाया कि जब राष्ट्र की सुरक्षा, ईमानदारी और जनता की सेवा साथ हों—तो भारत का रास्ता किसी बाधा से रुक नहीं सकता।

जबलपुर की स्नेहलता पटेल बनीं SIR अभियान की मिसाल, बेहतरीन काम पर मिला आसमान में उड़ने का तोहफ़ा

(जीएनएस)। जबलपुर में चल रहे मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान एक महिला सुपरवाइजर ने ऐसा काम कर दिखाया, जिसने पूरे जिले का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। स्नेहलता पटेल, जो बीएलओ सुपरवाइजर की ज़िम्मेदारी संभाल रही थीं, अपने अधीन आए सभी बूथों के गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन सबसे पहले पूरा करने वाली अधिकारी बनीं। जिला प्रशासन ने उनके इस बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें एक ऐसा सम्मान दिया जिसने उनकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में एक नया अध्याय जोड़ दिया। प्रशासन ने उन्हें पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा के माध्यम से जबलपुर से कान्हा और बांधवगढ़ तक हवाई यात्रा का विशेष अनुभव कराने का फैसला किया। हेलीकॉप्टर में बैठने का यह क्षण उनके लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक सपना पूरा होने जैसा था, जिसे वे कभी दूर से देखने के बावजूद अपने जीवन का हिस्सा नहीं मानती थीं।

जबलपुर प्रशासन के लिए यह अभियान सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं बल्कि एक ऐसा सामूहिक प्रयास रहा, जिसमें ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले हर कार्यकर्ता

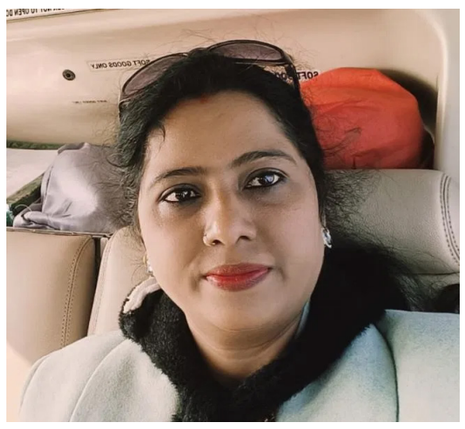

ने अपनी क्षमता से अधिक योगदान देने की कोशिश की। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने स्नेहलता पटेल के काम की सराहना करते हुए कहा कि प्रशासन बीएलओ और सुपरवाइजरों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार पहल कर रहा है। नकद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और तनाव कम करने के लिए मूवी टिकट जैसी योजनाओं के बाद यह हवाई सफर एक अनोखा संदेश था—कि मेहनत और समर्पण का पुरस्कार केवल कागज़ पर नहीं, अनुभवों में भी दिया जा सकता है। कलेक्टर ने यह भी बताया कि SIR के काम को समय-सीमा में पूरा कराने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, राजस्व अमले, नगर निगम की टीमों और प्रशासनिक कर्मचारियों को पूरे मनोयोग से सक्रिय किया गया और यही कारण है कि जिले में काम तेजी से आगे बढ़ सका।

स्नेहलता पटेल ने अपने अनुभव को याद करते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर की उड़ान उनके लिए जैसे किसी सपने का सच होना था। उन्होंने बताया कि उन्होंने हमेशा हेलीकॉप्टर को दूर से देखा था, कभी पास जाकर छुआ तक नहीं था, और उसके भीतर बैठकर आसमान में उड़ना तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। कलेक्टर द्वारा दिया गया यह उपहार उनके लिए एक खास भावनात्मक संबल बन गया, जिसने न सिर्फ उनके काम को मान्यता दी बल्कि उन्हें यह महसूस कराया कि प्रशासनिक तंत्र में मेहनत करने वालों को देखा और सराहा भी जाता है। यह सम्मान उनके लिए सिर्फ व्यक्तिगत खुशी नहीं, बल्कि अपनी टीम और पूरे अभियान के प्रति एक नई जिम्मेदारी की भावना से भी भरा हुआ था।

SIR अभियान के दौरान स्नेहलता के अधीन कुल 10 बूथ थे और इन बूथों में 7,706 मतदाता दर्ज थे। फॉर्म वितरण से लेकर गणना पत्रकों की ऑनलाइन एंट्री तक, हर प्रक्रिया को बैठकर संभालना और समय से पहले पूरा करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण था। फिर भी उन्होंने अपनी टीम के साथ वह काम कर दिखाया, जिसे जिले में सबसे पहले शत-प्रतिशत पूरा माना गया। जबलपुर की यह उपलब्धि पूरे जिले के अभियान के लिए प्रेरणा बन गई और प्रशासन के स्तर पर यह संदेश गया कि लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, समर्पण और टीमवर्क के साथ पूरा किया जा सकता है। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने कहा कि पूरे जिले में लगभग 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और आने वाले दो से तीन दिनों में शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि समीक्षा बैठक के बाद सभी टीमों को एक बार फिर फील्ड में सक्रिय किया गया है। प्रशासन की ओर से यह प्रयास सुनिश्चित किया जा रहा है कि अंतिम मतदाता तक की जानकारी समय पर अपडेट हो जाए ताकि चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची दोनों अधिक सटीक और पारदर्शी बन सकें।

जिले में कुल 19 लाख 25 हजार 472 मतदाता दर्ज हैं, जिनमें से अब तक 14 लाख 12 हजार 151 मतदाताओं के गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। यह आंकड़ा 73.34 प्रतिशत कार्य का प्रतिनिधित्व करता है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किसी भी स्तर पर ढिलाई की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी और यही कारण है कि SIR अभियान में तेजी देखने को मिल रही है। अभियान में उत्कृष्ट काम कर रहे बीएलओ और सुपरवाइजरों में उत्साह का संचार हुआ है और स्नेहलता पटेल जैसे उदाहरणों ने यह साबित कर दिया है कि जब जमीनी स्तर के लोग अपनी ज़िम्मेदारी को मिशन की तरह निभाते हैं, तो प्रशासनिक प्रणाली भी नई उड़ान भरती है।

हरिद्वार में पहली बार अमृत स्नान के साथ अर्द्धकुंभ की भव्य तैयारी चार महीने तक आध्यात्मिक संगम में डूबा रहेगा उत्तराखंड

(जीएनएस)। हरिद्वार के घाट, जहां सदियों से गंगा की धारा के साथ असंख्य कहानियाँ बहती रही हैं, अब एक नए अध्याय की तैयारी में हैं। वर्ष 2027 की शुरुआत उस पवित्र दृश्य के साथ होगी जब पहली बार अर्द्धकुंभ में अमृत स्नान आयोजित किए जाएंगे। 1 जनवरी 2027 से 30 अप्रैल 2027 तक चलने वाला यह चार महीने का महायज्ञ सिर्फ धार्मिक आस्था का नहीं, बल्कि परंपरा, अनुशासन और विशाल व्यवस्थाओं का भी अद्भुत संगम बनेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डामकोटी में तेरह अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठक की, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि इस बार का अर्द्धकुंभ कुंभ की भव्यता से कम नहीं होगा। इस निर्णय का संत समाज ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया, क्योंकि आधिकारिक घोषणाओं के बिना वे तैयारियाँ शुरू करने से हिचक रहे थे। अब जब तारीखें निश्चित हैं, अखाड़ों में एक नई हलचल दिखने लगी है। इस बार दस प्रमुख स्नान होंगे, जिनमें सबसे अधिक ध्यान तीन अमृत स्नानों पर रहेगा। इन्हें पहले 'शाही स्नान' कहा जाता था, लेकिन महाकुंभ 2025 के बाद से इन्हें अमृत स्नान का नाम दिया गया। इस बार स्नानों की संख्या पिछले कुंभ से कम है—2021 में हुए कुंभ में चार शाही स्नान हुए थे, जबकि इस अर्द्धकुंभ में तीन अमृत स्नान होंगे। इन तीन पवित्र स्नानों की तिथियाँ

अत्यंत महत्वपूर्ण हैं—

पहला अमृत स्नान 6 मार्च 2027 को महाशिवरात्रि पर,

दूसरा 8 मार्च 2027 को अमावस्या पर,

और तीसरा 14 अप्रैल 2027 को मेष संक्रांति तथा वैशाखी के पावन अवसर पर।

बाकी के सात स्नान भी धर्मपरायण जनसमूह के लिए उतने ही महत्वपूर्ण होंगे। 14 जनवरी की मकर संक्रांति से लेकर 20 अप्रैल की चैत्र पूर्णिमा तक, हर स्नान पर्व का अपना अलग आध्यात्मिक महत्व है और हरिद्वार इन्हीं तिथियों में लाखों श्रद्धालुओं से ढका रहेगा।

सबसे बड़ी चुनौती अखाड़ों की व्यवस्था है, और प्रशासन ने इस पर स्पष्ट नीति बनाई है। हर अखाड़े को स्नान के लिए बराबर समय—लगभग 30 मिनट—दिया जाएगा। एक अखाड़े के स्नान पूर्ण होने और घाट की सफाई के बाद ही अगला अखाड़ा नदी में प्रवेश करेगा। यह अनुशासन न सिर्फ भीड़ नियंत्रण में मदद करेगा, बल्कि सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने में भी अहम होगा।

बैठक में यह भी तय किया गया कि सरकार संत समाज के सुझावों को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। मुख्यमंत्री धामी ने सभी संतों को शॉल और फूलमालाओं से सम्मानित करते हुए कहा कि कुंभ साधु-संतों की सहभागिता से ही पूर्ण और पवित्र माना जाता है, इसलिए उनकी हर सुझाव को सम्मिलित करके योजना को आगे बढ़ाया जाएगा।

संतों की ओर से भी इस अर्द्धकुंभ को पूर्ण कुंभ के समान भव्य बनाने की सहमति मिली। सभी तेरहों अखाड़ों के सचिव बैठक में मौजूद रहे और उन्होंने प्रशासन के साथ मिलकर व्यवस्था बनाने के लिए सहयोग का आश्वासन दिया। आने वाले महीनों में हरिद्वार की धरती पर तंबुओं, शिविरों, रसोइयों, यात्रियों के आवासों और सुरक्षा की विशाल रूपरेखा जमीन पर उतरने लगेगी।

रांची में महिला को 'संकट-प्रेत' का डर दिखाकर 15 लाख के गहने लूटे, ठगों ने रची दिल दहला देने वाली चाल

(जीएनएस)। रांची के नामकुम इलाके में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घटी, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। रानी देवी नाम की एक साधारण गृहिणी—जो पहले ही अपने पति और छोटे बेटे की मौत का दर्द झेल चुकी थीं—एक ऐसी ठगी का शिकार हो गईं, जिसमें धोखाधड़ी के साथ-साथ इंसानी कमजोरी और अंधविश्वास का क्रूर फायदा उठाया गया।

शुक्रवार की सुबह रानी देवी अपने घर से थोड़ी दूर सब्जी लेने बाजार निकली थीं। सब कुछ सामान्य था—जब तक कि बाजार के किनारे दो अनजाने चेहरे उनके पास नहीं आए। पहले उन्होंने किसी घर का पता पूछा, फिर बातचीत शुरू हुई। कुछ ही मिनटों में, जैसे वे उनकी पूरी जिंदगी जान चुके हों, उनमें से एक युवक ने कहा—

"माताजी, आपके चेहरे पर गहरा दुख दिख रहा है आपके घर पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है आपके बड़े बेटे की जान को खतरा है। उसके साथ किसी भी समय अनहोनी हो सकती है।"

यह सुनते ही रानी देवी का दिल दहल गया। पति और छोटे बेटे को खो चुकी महिला का भय तुरंत जाग उठा। वही भय, जिसे इन शातिर ठगों ने हथियार बना लिया था।

इसके बाद शुरू हुई वो कहानी, जो ठगी से ज्यादा एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का केस लगती है। दोनों युवकों ने कहा कि उनके पास "उपाय" है—एक ऐसा उपाय जिससे रानी देवी के घर की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी, और उनके बेटे की जिंदगी सुरक्षित हो

जाएगी। डर और विश्वास के मिश्रित भाव में घिरी महिला उनकी बातों में गहराई से उलझती चली गईं।

ठगों ने उनसे कहा कि घर के सारे गहने लाकर दें। उन्हें "शुद्ध" किया जाएगा, फिर उन्हें एक पोटली में बांधकर दिया जाएगा। रानी देवी को बस उस पोटली को लेकर 51 कदम बिना पीछे देखे चलना था, फिर वापस आकर गहने घर में रख देने थे। यह सुनते ही महिला को लगा कि यह कोई धार्मिक प्रक्रिया है, कोई तांत्रिक उपाय, जो शायद उनके परिवार को बचा ले।

घर जाकर रानी देवी ने बिना किसी संदेह के अपने कीमती गहने—लगभग 15 लाख रुपये के—पोटली में बांधे और वापस उन युवकों तक पहुंच गईं। उसने गहने उन्हें सौंप दिए और जैसे कहा गया था, वैसे ही 51 कदम आगे चल पड़ीं।

लेकिन जब वे वापस लौटीं—न कोई पोटली थी, न कोई उपाय, न कोई युवक सिर्फ खुली सड़क और एक बेचैन, ठगी का शिकार महिला।

उनके हाथ से उनकी जिंदगी की बचत, उनकी आखिरी धरोहर, पलक झपकते ही गायब हो चुकी थी।

घबराई और टूट चुकी रानी देवी ने तुरंत नामकुम थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अब ठगों की तलाश में जुटी है, लेकिन मामला सिर्फ अपराध का नहीं—यह उस विश्वास के टूटने का है, जिसमें एक महिला ने अपनी पूरी दुनिया दांव पर लगा दी थी।

यह घटना सिर्फ एक पुलिस केस नहीं। यह चेतावनी है। यह समाज में फैले अंधविश्वास, मानसिक आघात और अपराधियों द्वारा उसका फायदा उठाने की सच्ची, दर्दनाक तस्वीर है।

बेंगलुरु में शुरू हुआ भारत का सबसे उन्नत HCP विश्लेषण केंद्र, बायोफार्मा उद्योग को मिली नई दिशा

(जीएनएस)। भारत की वैज्ञानिक यात्रा में एक और महत्वपूर्ण अध्याय उस समय जुड़ गया, जब साइटिवा और वीडा लाइफसाइंसेज की साझेदारी से बेंगलुरु में अत्याधुनिक हॉस्ट सेल प्रोटीन सर्विसेज सेंटर की शुरुआत हुई। यह उद्घाटन सिर्फ एक नए भवन या प्रयोगशाला का आरंभ नहीं था, बल्कि दवा विकास की उस लंबी प्रक्रिया में बड़ी छलांग थी, जिसमें हर कदम पर सटीकता, विश्वसनीयता और वैज्ञानिक अनुशासन की मांग होती है। नई दिल्ली से लेकर वैश्विक बायोफार्मा उद्योग तक, हर जगह इस केंद्र के खुलने को एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यह वह तकनीकी क्षमता देता है जो अब तक भारत में सीमित रूप में उपलब्ध थी। साइटिवा, जो लाइफ साइंसेज क्षेत्र में नवाचार और वैश्विक मानकों का पर्याय बन चुकी है, ने इस परियोजना में अपना तकनीकी अनुभव जोड़ा है। वहीं वीडा लाइफसाइंसेज, जो प्री-क्लिनिकल रिसर्च से लेकर क्लिनिकल ट्रायल्स तक बहुआयामी सेवाएं प्रदान करती है, इस केंद्र के संचालन को उद्योग की वास्तविक जरूरतों के हिसाब से ढालने का अनुभव रखती है। दोनों संस्थानों की यह साझेदारी दवा निर्माण क्षेत्र में उस भरोसे को मजबूत करती है, जिसकी नींव वैज्ञानिक सत्यापन और उच्च स्तरीय विश्लेषण पर टिकती है।

वीडा लाइफसाइंसेज के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. महेश भालगत ने उद्घाटन अवसर पर कहा कि बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर दवाओं की मंजूरी में एनालिटिकल

डेटा की भूमिका निर्णायक होती है और यह केंद्र उस डेटा को अत्यधिक विश्वसनीयता के साथ तैयार करेगा। उनके शब्दों में एक ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि दिखाई देती है, जो प्रयोगशाला की सीमाओं से आगे जाकर मरीज की सुरक्षा और दवा की प्रभावशीलता को केंद्र में रखती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मामूली-सी एचसीपी अशुद्धि भी दवा की गुणवत्ता को बदल सकती है और यही वजह है कि इस केंद्र का महत्व अत्यंत बढ़ जाता है।

इस सेंटर में स्थापित उन्नत तकनीकें भारत को वैश्विक स्तर की उन प्रयोगशालाओं की श्रेणी में ला खड़ा करती हैं, जहां मल्टीपल एट्रीब्यूट डिफरेंशियल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसी हाई-रेजोल्यूशन तकनीक मौजूद है। यह तकनीक दवाओं में मौजूद सूक्ष्म अशुद्धियों को इतनी बारीकी से पकड़ती है, जैसे कोई कलाकार महीन से महीन रेखा को भी पहचान ले। यही डेटा आगे जाकर रेगुलेटरी एजेंसियों के सामने दवा की सुरक्षा और प्रभावशीलता साबित करता है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और वैक्सीन जैसी अगली पीढ़ी की थेरेपीज इसी विश्लेषण पर टिकती हैं और इस कारण यह केंद्र अपने आरंभ के क्षण से ही उद्योग के लिए अपरिहार्य बन गया है।

साइटिवा के साउथ एशिया के जनरल मैनेजर मनोज कुमार आर. पणिक्कर ने इसे विज्ञान, उद्योग और उद्देश्य के संगम का क्षण बताया। उनके अनुसार, यह केंद्र केवल कंपनियों की मदद नहीं करेगा बल्कि बायोफार्मा क्षेत्र में वह नवाचार भी जन्म देगा, जिसे आने वाले दशक में भारत की वैज्ञानिक पहचान तय करनी है। उन्होंने कहा कि जब प्रयोगशाला का विज्ञान उद्योग की जरूरत से जुड़ता है, तब वह केवल दवाओं का निर्माण नहीं करता, बल्कि भविष्य का निर्माण करता है।

इस सेंटर की क्षमता का विस्तार इतना व्यापक है कि यह सिर्फ परीक्षण सुविधाएं ही नहीं देता, बल्कि दवा विकास की उन जटिल चरणों को भी सरल बनाता है, जिनमें कंपनियां अक्सर लागत और समय दोनों के दबाव में होती हैं। एचसीपी कवरेज, कैरेक्टराइजेशन और क्वांटिफिकेशन असेज जैसे परीक्षण इस केंद्र के प्रमुख स्तंभ होंगे और इनके माध्यम से कंपनियां अपने उत्पादन की गुणवत्ता को पहले से कहीं अधिक मजबूत आधार पर खड़ा कर सकेंगी। साइटिवा के बायोफार्मा इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट भी यही कहती है कि उद्योग अब डिजिटल और एआई-आधारित एनालिटिक्स की ओर तेजी से बढ़ रहा है, और यह केंद्र उसी बदलाव को गति देता है। वीडा लाइफसाइंसेज की पहले से मौजूद विशेषज्ञता—जो दवा विकास की प्रारंभिक खोज से लेकर रोगी तक दवा पहुंचने की अंतिम प्रक्रिया तक फैली होती है—अब इस केंद्र के साथ और अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। यह केंद्र सिर्फ भारतीय कंपनियों को ही नहीं, वैश्विक बायोफार्मा नेटवर्क को भी भारत की ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि यहाँ उपलब्ध तकनीकें और वैज्ञानिक प्रशिक्षण विश्व मानकों के बराबर हैं।

इस पूरी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत अब दवा निर्माण और परीक्षण के उस दौर में प्रवेश कर रहा है, जहां वह सिर्फ वैश्विक मांग का उपभोक्ता नहीं, बल्कि विश्वस्तरीय समाधानों का प्रदाता बन रहा है। बेंगलुरु का यह एचसीपी सर्विसेज सेंटर उस दिशा में उठाया गया एक मील का पत्थर है।

तीन राज्यों के विकास को मिलेगी नई रफ्तार, एडीबी देगा 800 मिलियन डॉलर का बड़ा ऋण पैकेज

(जीएनएस)। भारत के आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे की मजबूती को लेकर शुक्रवार का दिन बेहद अहम साबित हुआ, जब नई दिल्ली में केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच 800 मिलियन डॉलर से अधिक के तीन महत्वपूर्ण ऋण समझौते हुए। इन समझौतों के साथ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वे परियोजनाएँ नई गति पकड़ने वाली हैं, जिन पर राज्य सरकारें लंबे समय से फोकस कर रही थीं। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया कि इन ऋणों के माध्यम से न केवल बिजली वितरण और मेट्रो रेल जैसी शहरी परियोजनाओं को नई ऊर्जा मिलेगी, बल्कि युवा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में भी बड़ा निवेश होने वाला है। समझौते के हस्ताक्षर समारोह में भारत सरकार की ओर से आर्थिक मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव (एडीबी एवं जापान) ने एडीबी के साथ वार्ता का नेतृत्व किया, जबकि अंतिम दस्तावेज़ों पर विभाग के उप-सचिव सौरभ सिंह और एडीबी की ओर से भारत में मिशन की निदेशक मियो ओका ने हस्ताक्षर किए। यह वो क्षण था जब कागज़ पर दर्ज हुई इन संख्याओं ने सिर्फ रकम का रूप नहीं लिया, बल्कि उन हजारों लोगों की उम्मीदों का भी प्रतिनिधित्व किया, जिनके जीवन पर इन परियोजनाओं का सीधा प्रभाव पड़ने वाला है।

महाराष्ट्र को इस पैकेज का सबसे बड़ा

हिस्सा मिला है। राज्य की बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए 500 मिलियन डॉलर का भारी-भरकम ऋण स्वीकृत किया गया है। महाराष्ट्र लंबे समय से बिजली वितरण में बढ़ते दबाव, तकनीकी नुकसान और ग्रामीण–शहरी अंतर को कम करने की चुनौती का सामना करता आया है। इस कार्यक्रम के जरिए ट्रांसफॉर्मेशन, स्मार्ट मीटरिंग, नेटवर्क मॉडर्नाइजेशन और उपभोक्ताओं को विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा सुधार किया जाएगा। यह निवेश न केवल वितरण नेटवर्क को मजबूत करेगा बल्कि आने वाले वर्षों में उद्योग, किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की स्थिरता भी बढ़ाएगा।

मध्य प्रदेश को इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 190 मिलियन डॉलर से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इंदौर, जो लगातार देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल होता आया है, अब आधुनिक सार्वजनिक परिवहन के नए युग में प्रवेश कर रहा है। मेट्रो रेल सिर्फ एक परिवहन सुविधा नहीं होगी, बल्कि शहर की अर्थव्यवस्था, यातायात दबाव और पर्यावरणीय संतुलन पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। इस फंड से कोर स्ट्रक्चर, ट्रैक सिस्टम, ऊर्जा आपूर्ति और मेट्रो संचालन जैसी जरूरी आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। इंदौर की तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या और व्यावसायिक गतिविधियों को देखते हुए यह निवेश आने वाले दशकों तक शहर की जरूरतों को पूरा करेगा।

गुजरात को कौशल विकास कार्यक्रम के लिए लगभग 110 मिलियन डॉलर का समर्थन मिला है। राज्य पहले से ही उद्योग, उत्पादन और तकनीकी नवाचार का प्रमुख केंद्र रहा है, और अब यह राशि युवाओं को नई तकनीकों, उभरते व्यवसायों और आधुनिक कार्यस्थल की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एडीबी की यह सहायता उन कार्यक्रमों को मजबूती देगी, जो युवाओं को रोजगार से जोड़ने में मदद करते हैं और उद्योगों को प्रशिक्षित मानव संसाधन प्रदान करते हैं। कौशल विकास में इस निवेश का प्रभाव आने वाले वर्षों में गुजरात की औद्योगिक क्षमता को और अधिक ऊँचाइयों पर ले जाएगा।

इन सभी ऋणों का विशेष पहलू यह है कि ये तीनों राज्यों की जरूरतों के बिल्कुल अनुरूप हैं। एक राज्य में बिजली वितरण सुधार, दूसरे में मेट्रो विस्तार और तीसरे में मानव संसाधन विकास—ये तीनों क्षेत्र उस व्यापक विकास दृष्टि का हिस्सा हैं, जो भारत को तेज़, टिकाऊ और समावेशी वृद्धि की दिशा में ले जा रही है। एडीबी ने अपने बयान में कहा है कि भारत की विकास योजनाओं में सहयोग देना उसके लिए प्राथमिकता है, और ये समझौते उस भरोसे और साझेदारी का प्रतीक हैं जो वर्षों से दोनों पक्षों के बीच बनी हुई है।

इन समझौतों के साथ यह साफ है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की ऊर्जा क्षमता, मध्य प्रदेश की शहरी परिवहन व्यवस्था और गुजरात की कौशल शक्ति, तीनों नई दिशा और रफ्तार हासिल करने वाले हैं। यह ऋण महज़ वित्तीय मदद नहीं बल्कि विकास की वह धड़कन है, जिसकी गूंज आने वाले वर्षों तक महसूस की जाएगी।